सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
You Tube
Title Code : DELHIN28985.
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 01, अंक 348, नई दिल्ली । सोमवार, 26 फरवरी 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जितना और हारना यह तो आपकी सोच पर निर्भर करता है मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी।

03 टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड हटे, सिंघु बॉर्डर पर जर्सी बैरियर...
06 जरूरी है बेल कानून...
08 प्रधानमंत्री दुर्ग जिले की रेलवे अधोसंरचना को देंगे करोड़ों रुपयों की सौगात

क्या दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी अन्य राज्यों की तरह जनता की सड़कों पर सुरक्षा के प्रति कदम उठाएंगे या राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बनवाने में बने रहेंगे सहयोगी, जनता का सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़को पर गैर कानूनी तरीके से चलने वाले अनगिनत ई रिक्शों, निजी और बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों द्वारा व्यवसायिक गतिविधियां और जाम लगाने की जानकारी परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और आला अधिकारी के साथ प्रवर्तन शाखा (दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस) वालो की जानकारी में है पर फिर भी नही करते कोई कानूनी कार्रवाई। परिवहन विभाग और प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारियों के द्वारा दिल्ली की जनता की सुरक्षा से अधिक राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक बनवाना ज्यादा जरूरी है जिस कारण उच्चतम न्यायालय भारत, दिल्ली उच्च न्यायालय और गैजेट नोटिफिकेशन जारी होने पर भी वह सभी अपनी आखों पर पट्टी और कानो में रूई डाल कर जनता की सुरक्षा के प्रति दिल्ली में गैर कानूनी तरीके से चलने और जाम लगाने वाले वाहनों पर सख्त कानूनी कार्यवाही के आदेश नही देते।

दिल्ली की जनता को अवगत करा दे सुरक्षा के प्रति कार्यवाही करवाने के प्रति कार्यरत प्रवर्तन शाखा के प्रमुख (दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग) **भारत देश की राजधानी दिल्ली में जनता की सुरक्षा के प्रति सजगता दिखाने से अधिक सरकारी खजाने में जनता से कैसे अधिक से अधिक राजस्व जमा करवा पाए और राजनीतिक दलों के वोट बैंक सुरक्षित रखवा पाए के दायित्व में जुड़े हैं।**

कानपुर

कानपुर में अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा पर होगी कार्रवाई

कानपुर में अलग-अलग मार्गों पर अवैध ई-रिक्शा को चलाया जा रहा है। एक ही रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट को बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शे चल रहे हैं।

कही-कही एक ही नंबर के ई-रिक्शे शहर में अलग अलग जगह पर चलाए जा रहे हैं. जिसके चलते शहर की हर सड़क पर ई-रिक्शे नजर आ रहे हैं और यातायात को बाधित कर रहे हैं। एक ई-रिक्शे के रजिस्ट्रेशन नंबर पर कई ई-रिक्शे चलाए जा रहे हैं। ऐसे कई ई-रिक्शों को देखा गया है, जिसको लेकर अब स्मार्ट सिटी की तरफ से सड़कों पर सॉफ्टवेयर और कैमरों से ऐसे वाहनों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें चिन्हित कर सॉफ्टवेयर कंट्रोल रूम में संदिग्ध वाहनों की जानकारी देगा।

यातायात को ठीक करने और अवैध ई-रिक्शा के रोकथाम के लिए कानपुर जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने संयुक्त बैठक कर इस पर लगाम लगाने की ठान ली है और संभागीय परिवहन विभाग, कानपुर नगर निगम और पुलिस के संयुक्त होकर कार्यवाही और यातायात को बेहतर करने के लिए एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। कैमरा सड़कों पर नजर रखते हुए ऐसे वाहनों को चिन्हित कर लेगा और साथ ही पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंधित मार्गों पर उन वाहनों को नही जाने के निर्देश भी दिए है। अवैध वाहनों और ई-रिक्शों को संचालित करने वालों को भी चिन्हित कर धारा 336 और 151 में कार्यवाही करने की भी बात कही है।

इंदौर

इंदौर में 3 मार्च से नए ई-रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर रोक

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय इंदौर ने ई-रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय के बाद लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा के अनुसार ई-रिक्शा चालकों द्वारा निर्धारित रूटों पर वाहन नहीं चलाने, अव्यवस्थित तरीके से वाहन चलाने, क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने से शहर की यातायात प्रबंधन व्यवस्था में गड़बड़ा हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2 फरवरी को हुई जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक माह 3 मार्च के बाद इंदौर में नए ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी जाएगी। आरटीओ द्वारा बीते 9 फरवरी को यात्री ई-रिक्शा डीलरों की एक बैठक आयोजित की गई थी और उन्हें बताया गया कि वे ई-रिक्शा के शेष स्टॉक सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराएं। डीलरों को कहा गया कि आरटीओ कार्यालय को चेसिस नंबर सहित जानकारी दी जाए।

इंदौर नगर निगम ने शहर में ई-रिक्शा के खतरे को नियंत्रित करने के लिए एक नीति लाने का फैसला किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि वे ई-रिक्शा के लिए नीति और प्रोटोकॉल तैयार करने पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वे यातायात के मामले में शहर में खतरा पैदा कर रहे हैं। आईएमसी ने पहले ही ई-रिक्शा के लिए अलग-अलग रूट तय कर लिए हैं।

इंदौर शहर में ट्रैफिक फ्लो को सुचारू बनाने के लिए ई-रिक्शा के नए रजिस्ट्रेशन पर परिवहन कार्यालय इंदौर ने रोक लगा दी है और उनके लिए नए रूट बनाने का फैसले किया है। इसका ई-रिक्शा चालक संघ ने विरोध किया और करते 21 फरवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

लुधियाना

बिना नंबर के चल रहे ई-रिक्शा को ट्रैफिक पुलिस द्वारा 15 मार्च तक अल्टीमेटम

लुधियाना की सड़कों पर बिना नंबर के चल रहे ई-रिक्शा को ट्रैफिक पुलिस द्वारा 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जो ई-रिक्शा 15 मार्च के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चलते हुए दिखाई दिए तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ट्रैफिक पुलिस शहर में बिना ट्रेड सर्टीफिकेट के ई-रिक्शा बेचने वाले डीलरों की भी पहचान करेगी ताकि सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे ई-रिक्शा पर नकेल कसी जा सके। लुधियाना में ई-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए आज 17 नवंबर, शनिवार को ट्रैफिक विभाग की ए.डी.सी.पी. गुरप्रीत कौर पुरेवाल ने ई-रिक्शा डीलरों के साथ अपने कार्यालय में बैठक कर स्पष्ट हिदायत जारी की है कि वे ई-रिक्शा बेचते समय ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दें और उसे टैंपरेरी नंबर जरूर अलॉट करें जो सिर्फ एक महीने के लिए ही वैध रहेगा।

उन्होंने डीलरों को यह भी हिदायत दी है कि उनके द्वारा बेचे गए पुराने ई-रिक्शा जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसकी पूरी सूची बनाकर विभाग के पास जमा कराई जाए। इसके बावजूद अगर किसी ई-रिक्शा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में डीलर की गलती सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से भी पुलिस गुरेज नहीं करेगी। जिस ई-रिक्शा डीलर के पास ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं, वह ई-रिक्शा नहीं बेच सकता। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस डीलरों के शोरूम में जाकर उनकी पहचान करेगी।

जयपुर

ई-रिक्शा वहीं चला सकेगा जिसके नाम होगा रजिस्ट्रेशन

जयपुर मे पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यातायात एवं प्रशासन प्रीति चंद्रा के निर्देशन और डीसीपी लक्ष्मण दास के नेतृत्व में शनिवार 17 फरवरी को पुलिस आयुक्त कार्यालय में ई-रिक्शा संचालकों और अन्य वाहन यूनियनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में ई-रिक्शा व अन्य वाहन चालकों को जागरूकता को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गये। आने वाले सप्ताह से यातायात पुलिस एवं ई-रिक्शा एवं अन्य वाहन संघ के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

ई-रिक्शा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सभी ई-रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा चलाते समय अपना पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। ई-रिक्शा के लिए चालक के नाम पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। सभी ई-रिक्शा चालकों के पास वाहन के अनुसार लाइसेंस होना आवश्यक है। ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ई-रिक्शा चालान के संबंध में समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें और उसके बाद आरटीओ से ही चालकों का लाइसेंस प्राप्त करें। यदि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति वाहन चलाता पाया गया तो वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सड़क के बायीं ओर यात्रियों को चढ़ाएगा और छोड़ेगा। सभी प्रकार के धीमी गति के वाहन सड़क के बाईं ओर एक लेन में चलेंगे।

भारत की राजधानी दिल्ली में जहां गैर कानूनी तरीके से चलने और जाम लगाने वाले वाहनों पर पाबन्दी लगाना और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अति आवश्यक है पर दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी और प्रवर्तन शाखा प्रमुख विशेष आयुक्त परिवहन एवम्‌ दिल्ली यातायात पुलिस को आम जनता की छोटी सी गलती पर राजस्व वसूल करवाना जरूरी लगता है पर इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं।

जल्द ड्राइविंग लाइसेंस में ई रिक्शा की तरह ई कार्ट और ऑटो (3 पहिया) की अलग श्रेणी नज़र आएगी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दें पहले भारत देश में एलएमवी कमर्शियल, आटो, टैक्सी की अलग श्रेणी थी और उसी श्रेणी में ही ड्राईवर बेज भी लेना अनिवार्य था पर उच्चतम न्यायालय की एकल बेंच के द्वारा एक वाहन मालिक द्वारा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम ना देने के खिलाफ केस में दिशा निर्देश जारी किया था की एक ही श्रेणी के वाहनों में प्राइवेट एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होने पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर सकती जिसके बाद एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस में कमर्शियल, ऑटो और टैक्सी श्रेणी को बंद कर परिवहन विभाग द्वारा एलएमवी के ही लाइसेंस पर कमर्शियल वाहनों को चलाने की इजाजत दे दी थी।

बजाज इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उच्चतम न्यायालय के एकल बेंच द्वारा जारी इस आदेश को डबल बेंच में विरोध दर्ज कर अपनी पिटीशन में बताया की ऑटो द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देकर एलएमवी श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर मिनी बस, टूरिस्टर कोच, टैक्सी चला रहे हैं और इससे दुर्घटना को बढ़ावा मिल रहा है और ऐसे वाहन मालिकों और चालकों को क्लेम देना और जनता को असुरक्षा प्रदान करना गलत है जिसे उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच द्वारा सही माना गया और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी किया की अप्रैल 2024 तक वह इस पर नोटिफिकेशन जारी कर दे नही तो स्वयं उच्चतम न्यायालय इस मामले में आदेश पारित कर देगा।

जानकार सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी द्वारा पता चला है की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्त को इस पर अपने विचार जल्द से जल्द भेजने का पत्र भेज दिया है और 30 अप्रैल से पहले या 30 अप्रैल को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वालो के लिए ई रिक्शा की तरह ही ई कार्ट और ऑटो (तीन पहिया) की श्रेणी एलएमवी लाइसेंस से अलग देखने को मिलेगी जिससे आने वाले समय यानी मई से ऑटो चलाने वाले सभी वाहन चालकों को ऑटो श्रेणी का अपना ड्राइविंग लाइसेंस अलग से लेना अनिवार्य होगा और एलएमवी का ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले ऑटो (तीन पहिया) से अपना ड्राइविंग स्किल टेस्ट नही दे पाएंगे।

रेलवे ने घटाया किराया, 50 किमी. यात्रा के लिए लगेंगे अब महज 10 रुपये, आदेश जारी

(दिल्ली सरकार कब घटायेगी करोना काल में करोना सेस लगा कर बढ़ाई कीमतें)

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय रेलवे बोर्ड ने जनरल टिकट का किराया कम कर दिया है। अब जनरल टिकट लेकर 50 किलोमीटर सफर करने के लिए मात्र 10 रुपए किराया देना होगा। यह पहले 30 रुपए था। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया है।

बताते चलें कि, कोरोना काल तक यही किराया था, लेकिन इसके बाद जब ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया, तो रेलवे ने किराया बढ़ाकर 10 से 30 रुपये कर दिया। रेलवे बोर्ड ने यूटीएस सिस्टम और यूटीएस एप में बदलाव करने का आदेश जारी कर दिया है। लोकल टिकट बुकिंग करने वाले आईआरसीटीसी के सॉफटवेयर में भी बदलाव आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दैनिक रेलयात्रा में तीन गुना पैसा चुका रहे मजदूरों और दैनिक यात्रियों को भारतीय रेलवे बोर्ड के इस फैसले से बड़ा लाभ होने जा रहा है। अब 50 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग मात्र 10 रुपए में आवाजाही कर सकेंगे। फिर चाहे जयपुर के रेलयात्री हों या भोपाल के।

दिल्ली के रेलयात्री हों या फरीदाबाद के। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि 50 से हर 10 से 15 किलोमीटर तक यात्रा करने पर 5 रुपए बढ़ जाता है। इसका मतलब यह कि अब 30 रुपए में यात्री 90 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे।

रेलवे ने कोरोना काल में लोकल ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में नामित कर दिया था। सामान्य ट्रेनों का संचालन भी बंद कर दिया गया था। इसके कारण इनका किराया 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गया था। एक्सप्रेस ट्रेनों का सबसे कम किराया 30 रुपए है। अब फिर से इसे सामान्य कर दिया है, तो यह किराया कम हो गया है। इससे देश के लाखों दैनिक यात्रियों को लाभ होने जा रहा है। ट्रेनों की श्रेणी बदलने से अन्य यात्रियों को भी लाभ हो सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार अभी तक इस सेवा के लिए प्रमुख रूप से तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई है...

परिवहन मंत्री दिल्ली का सपना करवाया सच और पूरा, स्टेज कैरिज क्षमता में कांट्रेक्ट कैरीज परमिट पर जारी किया प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम का पहला लाइसेंस

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली सरकार और खास तौर से परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की महत्वाकांक्षी प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम के तहत जल्द ही बसों का परिचालन शुरू करने के लिए परिवहन विभाग ने पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। विभाग ने बस सेवा शुरू करने के लिए आवेदन करने वाले तीन कंपनियों आवेग, चलो और उबर में से आवेग को लाइसेंस जारी कर दिया है। कंपनी को अप्रैल के अंत तक सड़क पर बसें उतार देने का समय दिया गया है। इस स्कीम में काम पर तेजी परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा जनवरी में ली गई बैठक के बाद आई है, जिन्होंने इस स्कीम के तहत जल्द से जल्द जाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था।

परिवहन विभाग के अनुसार अभी तक इस सेवा के लिए प्रमुख रूप से तीन कंपनियों ने रुचि दिखाई है और अपने दस्तावेज जमा कराए हैं। हालांकि तीन अन्य कंपनियां भी परिवहन विभाग के संपर्क में हैं मगर उनके अभी बात चल रही है। पहले इस स्कीम के तहत मार्च तक बसें सड़को पर उतार देने की योजना थी। जिस कंपनी को लाइसेंस मिला है उसे इस स्कीम के तहत 25 बसों का पहला बेड़ा सड़क पर लाना है। यह बसें 30 अप्रैल से पहले ही सड़कों पर उतारनी होंगी।

स्कीम के अनुसार जिस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, उसे कम से कम 25 बसों का फ्लीट संचालित करना होगा। बस के रूट और किराया आपरेटर खुद तय करेंगे और किराया डिजिटल माध्यम से लेना होगा। बसों के लिए सीट पहले ही बुक करनी होगी। बसों में यात्री को सीट मिलने की गारंटी होगी और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं। बसों में सुरक्षा के सभी इंतजाम और कुशल ड्राइवर रखने जरूरी है।

प्रधानमंत्री दुर्ग जिले की रेलवे अधोसंरचना को देंगे करोड़ों रुपयों की सौगात....

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर के 550 अमृत भारत स्टेशन के शिलान्यास के साथ-साथ रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से देश की जनता से जुड़ेंगे। दुर्ग जिले के रेल इतिहास का ये सबसे खास दिन साबित होगा जब दुर्ग जिले में 10 से अधिक विकास कार्यों की सौगात रेलवे क्षेत्र को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास और लोकार्पणों का स्थानीय स्तर पर एलईडी के माध्यम से अलग-अलग स्थान में वर्चुअल कार्यक्रम होगा, जिसमें जनता और स्थानीय कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्थानीय स्तर पर प्रातः 10:45 बजे कार्यक्रम प्रारंभ होगा इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12:20 बजे जुड़कर लोकार्पण शिलान्यास के साथ अपना उदबोधन देंगे। दुर्ग जिले में अलग-अलग स्थान पर वर्चुअल माध्यम से होने वाले कार्यक्रमों को लेकर रेलवे के अधिकारियों से समन्वय हेतु जिला महामंत्री सुरेंद्र कौशिक और जिला भाजपा उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार पाध्ये को प्रभार दिया गया है।

जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म नंबर 1 पर अंडरब्रिज के लिए कार्यक्रम होगा इसी प्रकार दुर्ग शहर में ही उरला और बघेरा के अंडरब्रिज का संयुक्त कार्यक्रम उरला में रेलवे क्रॉसिंग पर सिद्धेश्वर मंदिर के पास होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भिलाई नगर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसका कार्यक्रम भिलाई नगर रेलवे स्टेशन में ही संपन्न होगा। अहिवारा विधानसभा अंतर्गत सिरसा गेट भिलाई- 3 में अंडरब्रिज लोकार्पण और डी केबिन बीएमआई चरोदा के अंडरब्रिज की सुविधा भिलाई 3 चरोदा नगर निगम की जनता को मिलेगी, जिसका पृथक पृथक कार्यक्रम दोनों स्थान पर होगा। पाटन विधानसभा अंतर्गत कुम्हारी रेलवे क्रॉसिंग पर भी अंडरब्रिज की सौगात मिलेगी।

जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने आगे बताया कि दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत रसमडा स्टेशन के पास अंडरब्रिज और दल्लीराजहरा रूट पर रिसामा के पास अंडरब्रिज की सौगात मिलेगी, दोनों स्थानों पर पृथक पृथक कार्यक्रम होगा। साथ ही दल्लीराजहरा रूट पर ही कचान्दुर से पहले ग्राम परसदा के पास अंडरब्रिज की सुविधा ग्रामवासियों को मिल सकेगी। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में चहुंओर विकास की गंगा बह रही है। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विकास की धारा ना पहुंची हो। सड़क, रेलवे, उद्योग, विद्युत, सौर ऊर्जा सहित अनेक अनेक क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। राष्ट्र सेवा को ही मूल मंत्र मानकर जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए नरेंद्र मोदी सरकार लगातार कार्य कर रही है। मोदी की गारंटी देश में आज सबसे बड़ी गारंटी है।

इनसाइड

प्रेग नेंसी में मोबाइल रेडिएशन से दूरी बनाना जरूरी वरना शिशु को हो सकता है मेंटल प्रॉब्लम

अगर गर्भवती महिला के आसपास अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन है, तो उसके पेट में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है. यही नहीं, बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है. जानें, प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल रेडिएशन से अजन्मे बच्चे के विकास में क्या समस्या आ सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है. हम सभी सुनते आए हैं कि अधिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है. खासतौर पर प्रेग्नेंट महिला और उसके पेट मे पल रहे बच्चे के लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है. प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पेट में पल रहे बच्चे के विकास पर बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर डिलीवरी तक हो सकती है. केवल मां ही नहीं, अगर मां के आस पास लोग वायरलेस चीजों का अधिक इस्तेमाल कर रहे है तो इसका भी भ्रूण में पल रहे बच्चे पर खराब असर पड़ सकता है. मॉमजंक्शनमें छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में किए गए शोध में पाया गया है कि अत्यधिक मोबाइल रेडिएशन में अगर गर्भवती मां रहती है तो जन्म के बाद बच्चे को जीवन भर बिहेवियर प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है. यही नहीं, इसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे के मानसिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं.

वायरलेस डिवाइस कैसे करता है प्रभावित

दरअसल जब हम मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी तरह के वाइफाई या वायरलेस डिवाइस के संपर्क में आते हैं तो इससे हर वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स निकलते रहते हैं. ये वेव्स हमारे शरीर के डीएनए को डैमेज करने की क्षमता रखते हैं और हमारे शरीर में बन रहे जीवित सेल्स के मोलक्यूल्स को बदल सकते हैं. जिसका असर लॉग टर्म काफी खतरनाक हो सकता है. चूंकि भ्रूण हर वक्त ग्रोथ कर रहा है ऐसे में उसके डीएनए और लीविंग सेल्स आसानी से इसकी चपेट में आ सकते हैं. जिसका दूरगामी असर भी काफी खतरनाक हो सकता है.

क्या कहता है शोध

अलग अलग शोधों में पाया गया कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन अगर मां और बच्चा 24 घंटे मोबाइल रेडिएशन के बीच हैं तो बच्चे की मेमोरी, ब्रेन ग्रोथ और बिहेवियर में खतरनाक रूप से समस्या आ सकती है. शोधों में यह भी पाया किया गया कि प्री और पोस्ट डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है. यही नहीं, बच्चे की भाषा, संचार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

इस तरह करें बचाव

- घर में जहां तक हो सके वाई फाई या ब्लूटूथ उपकरणों का इस्तेमाल कम करें.
- बेहतर होगा अगर आप मोबाइल की बजाय लैंड लाइन फोन का इस्तेमाल करें.
- रेडियो, माइक्रोवेव, एक्सरे मशीन आदि से दूरी बनाएं.
- मोबाइल टावर आदि के आस पास घर ना लें.

गर्भावस्था में मोबाइल के नुकसान

-गर्भवती महिलाओं में रेडिएशन से मस्तिष्क की गतिविधि पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिससे थकान, चिंता और नींद में रुकावट पैदा होती है.

-गर्भावस्था के दौरान रेडियो वेव्स के लगातार संपर्क से आगे जाकर कैंसर का खतरा बन सकता है.

-मां गर्भावस्था के दौरान फोन का अधिक इस्तेमाल करे या काफी करीबी लोग घर पर इसका इस्तेमाल करें तो बच्चे के व्यवहार में 50 प्रतिशत बदलाव देखने को मिलता है.

-ऐसे बच्चे अधिक एग्रेसिव और हाइपरटेंशन के पेशेंट हो जाते हैं.

क्या एग फ्रीज कराने से मेनोपॉज जल्दी होता है?

6 मिथक जिस पर लोग करते हैं यकीन, डॉक्टर से जानें सच्चाई

आजकल करियर पर फोकस करने वाली महिलाओं के बीच अपने एग को फ्रीज कराने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. गर्भ धारण करने की इस तकनीक ने बढ़ती उम्र में भी मां बनने की राह आसान कर दी है. हालांकि, आज भी एग फ्रीजिंग को लेकर कुछ मिथक हैं, जिन पर लोग यकीन कर लेते हैं.

आजकल एग फ्रीजिंग वे महिलाएं करवा रही हैं, जो अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं. जल्द मां बनना नहीं चाहती हैं, क्योंकि मां बनने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है और फिर करियर पर फोकस कर पाने में समस्या आने लगती है. 20-30 साल की उम्र में युवतियां एग फ्रीज कराने का ऑप्शन चुन रही हैं. यह अधिक उम्र में प्रेग्नेंट होने का बेस्ट टेक्नीक है. साथ ही उनके लिए भी फायदेमंद हैं, जो लेट से मां बनना चाहती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक उम्र होने पर कई बार प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती हैं और अंडों की भी संख्या और क्वालिटी खराब हो जाती है. हालांकि, ये चलन जहां मेट्रो सिटीज में बढ़ रहा है, तो वहीं छोटे शहरों में रहने वाले लोग इस टेक्नीक से गर्भ धारण करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते. कुछ लोगों के अंदर तो एग फ्रीजिंग को लेकर ऐसी गलत धारणाएं या मिथक व्याप्त हैं, जिससे वे इसे कराने से बचते हैं. आइए जानते हैं एग फ्रीजिंग से संबंधित कुछ मिथ्स और फैक्टस के बारे में यहां.

मिथ्स 1: एग फ्रीजिंग प्रक्रिया दर्दनाक और समय लेने वाली है?

फैक्ट- आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. शोभा गुप्ता कहती हैं कि एग फ्रीजिंग की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक हार्मोन, दवा, इंजेक्शन आमतौर पर 8 से 11 दिनों के लिए दिन में एक या दो बार लिए जाते हैं. इस अवधि के दौरान, आपका शरीर दवा के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, इसकी निगरानी के लिए एक डॉक्टर 5-7 संक्षिप्त दौरों के साथ मरीज की जांच करता है. जब पेशेंट तैयार हो, तो डॉक्टर एग रिट्रीवल सर्जरी में व्यक्ति के अंडे निकालकर प्रक्रिया को पूरा करते हैं. "सर्जरी" शब्द डरावना लग सकता है. प्रक्रिया के इस भाग के बारे में तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टांके नहीं लगते हैं, कोई कट नहीं होता है और इसमें सिर्फ 15 मिनट लगता है. पूरी प्रक्रिया शुरू होने से लेकर खत्म होने तक लगभग दो सप्ताह का समय लेती है.

मिथ्स 2: एग फ्रीजिंग सिर्फ आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग या एलीट करियर वाली महिलाओं के लिए ही है?

फैक्ट- महिलाएं चिकित्सकीय और सामाजिक दोनों तरह के कारणों से अपने अंडे को फ्रीज कराने का विकल्प चुनती हैं. कई महिलाएं चिकित्सकीय निदान के कारण अपने अंडे फ्रीज कराती हैं तो कुछ आर्थिक तंगी, पार्टनर नहीं होने या अन्य कारणों से ऐसा करती हैं. बहुत सारे अलग-अलग कारण हो सकते हैं. वर्तमान परिदृश्य में, अधिकांश महिलाएं जो अपने अंडे फ्रीज करवाती हैं, वे ऐसा इसलिए करती हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक अपना सही जीवनसाथी नहीं मिल सका है.

मिथ्स 3: एग फ्रीजिंग एक सुरक्षित प्रक्रिया नहीं है?

फैक्ट- एग फ्रीजिंग आपके कुछ अंडों को इकट्ठा करके, फ्रीज करके और उन्हें अपने अंडाशय से संग्रहित करने की विधि है, ताकि आप बाद में गर्भवती होने के लिए उनका उपयोग कर सकें. आप निश्चिंत रहें कि एग फ्रीजिंग में स्वस्थ महिलाओं के लिए जटिलताओं का उच्च जोखिम नहीं होता है और इसे सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है.

मिथ्स 4: केवल यंग महिलाओं और युवतियों को अपने अंडे फ्रीज करने चाहिए?

फैक्ट- जरूरी नहीं कि हर महिला अपने अंडे फ्रीज कराए ही. इसके अलावा, एक डॉक्टर द्वारा अंडे को फ्रीज करने से पहले एक व्यापक चिकित्सा इतिहास लिया जाना चाहिए. एग फ्रीजिंग केवल तभी मदद कर सकता है, जब किसी को भविष्य में प्रजनन संबंधी समस्याएं होने की उम्मीद हो या यदि वे 30 के दशक के अंत और 40 के दशक की शुरुआत में बच्चे पैदा करने का इरादा रखती हों.

मिथ्स 5: एग फ्रीजिंग से मेनोपॉज जल्दी होता है?

फैक्ट- नहीं, एग फ्रीजिंग से समय से पहले मेनोपॉज नहीं होता है. हर महीने एक महिला का शरीर कई अंडे तैयार करता है, जो विकसित हो सकते हैं. एग फ्रीजिंग प्रक्रिया के दौरान, हम अंडों के उस पूरे सेट को काटते हैं, जो बदले में आपकी भविष्य की उर्वरता को प्रभावित नहीं करता है. एग फ्रीजिंग का मेनोपॉज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. यह एक आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित महिलाओं से संबंधित इशू है.

मिथ्स 6: एग फ्रीजिंग मुख्य रूप से सिंगल लोगों के लिए होता है?

फैक्ट- एग फ्रीजिंग सिर्फ सिंगल लोगों के लिए नहीं है. बहुत से लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और विवाह में भी अपने अंडे फ्रीज करवाते हैं. उदाहरण के लिए, कोई ऐसा करने का निर्णय तब ले सकता है, यदि वे एंडोमेट्रियोसिस या कैंसर के निदान के साथ इलाज के बाद संघर्ष कर रहे हैं. दूसरी बार, जब वे अभिवावक या मां देर से बनना चाहते हों, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए तैयार हों.

एग फ्रीजिंग के पहले और बाद में कैसा हो आपका खानपान? किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान, देखें पूरी लिस्ट

एग फ्रीजिंग के जरिए मां बनना कुछ महिलाओं को पसंद आ रहा है. खासकर, वे युवतियां इस प्रॉसेस को चुन रही हैं, जो शादी के तुरंत बाद ही मां बनने की बजाय करियर को तवज्जो देना चाहती हैं. यदि आपने एग फ्रीज कराया है तो उससे पहले और बाद में कैसी डाइट होनी चाहिए, इसके बारे में भी जानना बेहद जरूरी है. इससे हेल्दी प्रेग्नेंसी की राह आसान हो जाती है.

इन दिनों महिलाओं के बीच एग फ्रीजिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है. कई कारणों से युवतियां इसका सहारा लेती हैं जैसे आर्थिक अस्थिरता, करियर, साथी का ना होना, देर से शादी करना आदि. एग फ्रीजिंग उन महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना या बढ़ती उम्र में मां बनना चाहती हैं. इन दिनों सोशल एग फ्रीजिंग का चलन बढ़ गया है, जिसका मतलब है मेडिकल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए अंडे को संरक्षित करना. एग फ्रीजिंग का फायदा उन महिलाओं को सबसे ज्यादा होता है, जिन्हें कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है. इस ट्रीटमेंट की वजह से अक्सर अंडे (Egg) खत्म हो जाने के कारण महिलाएं भविष्य में मां नहीं बन पाती थीं. ऐसे में उन्हें एग फ्रीजिंग का काफी लाभ मिला है. हालांकि, एग फ्रीजिंग कराने के पहले, बाद में और अंडे को गर्भ में दोबारा डालने के बाद आपकी लाइफस्टाइल, डाइट सबकुछ अच्छी होनी चाहिए. इससे गर्भावस्था में कोई समस्या नहीं आती है. बच्चे का विकास भी सही तरीके से होता है.

एग फ्रीजिंग डाइट कब शुरू करनी चाहिए?

मदर्स लैप आईवीएफ सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर व आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. शोभा गुप्ता कहती हैं कि एग फ्रीजिंग के जरिए मां बनना चाहती हैं तो लाइफस्टाइल, डाइट सबकुछ हेल्दी होना चाहिए. शोध से पता चला है कि डाइट में बदलाव के साथ अंडे की गुणवत्ता में सुधार होने में लगभग 3 महीने लगते हैं. यदि आप भविष्य के लिए अपने अंडों को फ्रीज़ करने पर विचार कर रही हैं, तो अपनी प्रक्रिया से पहले अपने अंडों को सही आकार में लाने के लिए हेल्दी खानपान जरूरी है. इसके लिए आपको जल्द से जल्द फर्टिलिटी डाइटिशियन से संपर्क करना बेहद जरूरी हो जाता है. खानपान में हर समय महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का सेवन करना जरूरी हो जाता है.

एग फ्रीजिंग के बाद कैसी हो आपकी डाइट?

मदर्स लैप आईवीएफ सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर व आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. शोभा गुप्ता कहती हैं कि एग फ्रीजिंग के जरिए मां बनना चाहती हैं तो लाइफस्टाइल, डाइट सबकुछ हेल्दी होना चाहिए. शोध से पता चला है कि डाइट में बदलाव के साथ अंडे की गुणवत्ता में सुधार होने में लगभग 3 महीने लगते हैं...

अंडा पुनर्प्राप्ति (egg retrieval) के बाद स्वस्थ भोजन जैसे चिकन नूडल सूप, लीन प्रोटीन, फल और सब्जियां खूब खाएं. एग फ्रीजिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए जाने वाले एनेस्थीसिया के कारण कुछ महिलाओं को हल्की मतली का अनुभव हो सकता है. यदि आपके साथ ऐसा होता है, तब तक हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जब तक आप फिर से बेहतर महसूस न करने लगें.

इन चीजों को भी करें डाइट में शामिल

जिंक एक आवश्यक मिनरल है, जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के लिए महत्वपूर्ण है. अपने आहार में क्विनोआ को जरूर शामिल करें. इसके साथ ही काजू और दाल जिंक के अच्छे स्रोत हैं. विटामिन डी एक महत्वपूर्ण प्रजनन हार्मोन को नियमित करने और उत्पादन करने में बड़ी भूमिका निभाता है. अंडे का पीला वाला भाग, सैल्मन मछली, ट्राउट, सार्डिन और मशरूम जैसे खाद्य पदार्थ भी फायदेमंद होते हैं. सीधी धूप विटामिन डी का बेहतरीन स्रोत है. ओमेगा-3 एक आवश्यक फैटी एसिड है, जो हमारे आहार में पाया जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और आपके प्रजनन अंगों के आसपास सूजन को कम करने में मदद करते हैं. सीफूड के अलावा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट सहित प्लांट सोर्स में भी ओमेगा -3 होता है.

वीर नारी सम्मान से नवाजी गई 105 वर्षीय अलकारी देवी, गुमनामी में जिंदगी बिताते दुनिया को कह गईं अलविदा

परिवहन विशेष न्यूज

जहानाबाद :- जिले के हुलासगंज प्रखंड के लोदीपुर गांव की वीर नारी के सम्मान से नवाजी गई स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह की पत्नी अलकारी देवी इस महिने के 22 तारिख को गया स्थित मिलिट्री अस्पताल में अन्तिम सांस ली। यह विडंबना ही कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की ओर से विभिन्न देशों में अपनी वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल का परिचय देते हुए कई वार मेडल प्राप्त करने वाले स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह की पत्नी के अंतिम संस्कार में प्रशासन और सरकारी महकमा से कोई उपस्थित नहीं था। स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह जिनके वीरता और पराक्रम के किस्से कहानियां आज भी हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र में प्रचलित है। भारत को आजादी दिलाने की शर्त पर ब्रिटिश रॉयल सैनिक के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध में वे लड़े और अद्भुत पराक्रम करते हुए कई देशों में अपनी सेवा एक सैनिक के रूप में दिया। वीर योद्धा इंद्रदेव सिंह गुमनामी में ही दुनिया से विदा हो गए। उनकी 105 वर्षीय धर्मपत्नी अलकारी देवी उनके मेडल और उनकी यादों को सहेज कर रखी हुई थी लेकीन अंततः वे भी गुमनामी में ही इस महीने के 22 तारिख को दुनियां को अलविदा कह गई। ज्ञात हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाले इंद्रदेव सिंह को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विश्व योद्धा का प्रमाण पत्र और मेडल मिला लेकिन अपने ही देश में उनकी विधवा पत्नी का हाल तक जानने कोई राजनेता या प्रशासक सामने नहीं आए। उपेक्षा का दंश झेल रही स्वतंत्रता सेनानी की बेवा को अपने पति के अदम्य साहस और पराक्रम पर हमेशा गर्व रहा लेकिन नजरंदाजी कहें या शासन की भूल आज अपने ही जन्मस्थली में वीर योद्धा का एक आदमकद प्रतिमा तक कहीं नहीं लगा। बताया जाता है कि विश्व योद्धा स्वर्गीय इंद्रदेव सिंह के सेना छोड़ने से पहले उन्हें वर्ष 1944 में वर्मा अब म्यांमार में स्टार वार मेडल मिला। उन्होंने वियतनाम समेत लगभग आठ देशों में अपने युद्ध कौशल का पराक्रम दिखाया। 14 जनवरी 2004 को संसार से विदा हो गए । वर्ष 1995 में 8 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ के 50 में स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर इन्हें वैश्विक स्वतन्त्रता सेनानी एवं विश्व शांति दूत का उपमा देकर सम्मानित किया गया था। इंद्रदेव सिंह को विश्व योद्धा और उनकी पत्नी को वीर नारी का सम्मान मिला 1 लेकिन स्थानीय स्तर पर सरकार और प्रशासन के तरफ से कोई सम्मान नहीं मिला। इस संबंध में अपना दर्द बयां करते हुए इनके पुत्र डॉ द्वारिका शर्मा बताते हैं कि उन्हें इस बात का मलाल जरूर है कि उनके बाबूजी और वृद्ध मां को कोई नागरिक सम्मान नहीं मिला और न ही राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हुई। लेकिन अपने माता पिता के अच्छे परवरिश मिलने और एक राष्ट्रवादी सैनिक के पुत्र के रूप में मुझे जो पहचान मिली उससे अपने माता पिता पर हमेशा गर्व रहा है। देखा जाए तो कभी वीरता और देशप्रेम को वीर रस के कवियों ने अपने कलमो से उनमें प्राण भरा था आज सब जगह बेबसी नजर आती है।

गर्भ पर ग्रहों का प्रभाव

एक स्वस्थ गर्भ मे बच्चा लगभग 9 महीने और 9 दिन रहता है और अलग-अलग महीने में अलग-अलग ग्रह अपनी किरणों से गर्भ को प्रभावित करती हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप बच्चे के शरीर के भागो को विकसित करता है। अगर कोई ग्रह गर्भ मे पल रहे बच्चे के समय कमजोर है तो उपाय से उसको ठीक किया जा सकता है।

1. गर्भ से 1 महीने तक शुक्र का प्रभाव रहता है अगर गर्भावस्था के समय शुक्र कमजोर है तो शुक्र को मजबूत करने के उपाय करने चाहिए।

अगर शुक्र मजबूत होगा तो बच्चा स्वस्थ व सुंदर होगा। और उस समय स्त्री को स्वास्थ्यवर्धक व चटपटी चीजे खानी चाहिए।

देवी मां की पूजा उपासना करनी चाहिए। और इस समय के दौरान शास्त्रों में कुछ विशेष मंत्र बताए गए हैं जिनका जप करना चाहिए।

2. दूसरे महीने मंगल का प्रभाव रहता है। मीठा खा कर मंगल को मजबूत करें तथा लाल वस्त्र ज्यादा धारण करे। इस समय मंगल ग्रह के कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए।

3. तीसरे महीने गुरु का प्रभाव रहता है। दूध और केसर से बनी मिठाई या पकवान का सेवन करे तथा पीले वस्त्र ज्यादा धारण करे।

शास्त्रोक्त गुरु ग्रह के कुछ विशेष उपाय हैं उन्हें भी करना चाहिए।

4. चौथे महीने सूर्य का प्रभाव रहता है। फलों के रसों का सेवन करें तथा महरून वस्त्र ज्यादा धारण करे।

इस समय के दौरान सूर्य ग्रह के शास्त्रोंक्त उपाय जरूर करें।

5. पांचवे महीने चंद्र का प्रभाव रहता है।दूध और दही तथा चावल तथा सफ़ेद चीजों का सेवन करे तथा सफ़ेद वस्त्र ज्यादा धारण करे। और चंद्रमा के शास्त्रोक्त उपाय करें।

6. छटे महीने शनि का प्रभाव रहता है। कसैली चीजों केल्शियम और रसों के सेवन करे तथा आसमानी वस्त्र ज्यादा धारण करे। इस महीने में शनि ग्रह के कुछ विशेष उपाय जरूर करना चाहिए।

7. सातवे महीने बुध का प्रभाव रहता है। हरी सब्जियां, जूस और फलों का खूब सेवन करे तथा हरे रंग के वस्त्र ज्यादा धारण करे। और कुछ शास्त्र सम्मत बुध ग्रह के उपाय भी इस महीने में करने चाहिए। इस समय के दौरान प्रतिदिन श्री गणेश भगवान को 'दूर्वा' अर्पित करें

8. आठवे महीने गर्भ पर चंद्र का प्रभाव ज्यादा रहता है। इस समय सफेद वस्तुओं का प्रयोग ज्यादा करें। और ₹ऊं नमः शिवाय₹ मंत्र का जाप करें/ जल को हमेशा मंत्रों से अभिमंत्रित करके पिएं।

9. नौवें महीने सूर्य का प्रभाव रहता है। अतः इसके लिए गायत्री मंत्र का जप करें/इस दौरान घर में एक छोटा सा गायत्री यज्ञ-हवन करें। और सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करें।

ध्यान रहे जितना गर्भ ग्रहों की किरणों से तपेगा /और जितना शास्त्रोक्त नियमों का पालन होगा उतना ही बच्चा महान और मेधावी होगा और बच्चे का भविष्य अच्छा होगा।।

दिल्ली को बड़ी राहत देगी सरकार, रिंग रोड को जाम से मुक्त करने की योजना बनाने की तैयारी

रिंग रोड पर मजनू का टीला से लेकर हनुमान मंदिर तक लग रहे भयंकर जाम को दूर करने के लिए लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने अपने विभाग के अधिकारियों से योजना तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इस जाम की समस्या से निजात के लिए तुरंत राहत और दूरगामी दोनों तरह की योजना तैयार करने के लिए कहा है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। रिंग रोड पर मजनू का टीला से लेकर हनुमान मंदिर तक लग रहे भयंकर जाम को दूर करने के लिए लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने अपने विभाग के अधिकारियों से योजना तैयार करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इस जाम की समस्या से निजात के लिए तुरंत राहत और दूरगामी दोनों तरह की योजना तैयार करने के लिए कहा है।

इसी बीच स्वयं सेवी संस्था गुरू हनुमान सोसाइटी ऑफ भारत ने रिंग रोड पर पर लग रहे जाम को दूर करने का सुझाव दिया है। मुख्य सचिव नरेश कुमार को भेजे गए सुझाव में संस्था ने कई समाधान बताए हैं। इनके लागू होने पर राहत की उम्मीद की जा सकती है।

वाहन चालकों का छूट रहा पसीना

यहां बता दें कि रिंग पर जाम वाहन चालकों का पसीना छुटा रहा है। मजनू का टीला से लेकर हनुमान सेतु तक दोनों तरफ इस मार्ग पर भयंकर जाम लग रहा है। यहां का जाम राजघाट की ओर से मजनू का टीला आने वाले वाहन चालकों की बढ़ा रहा परेशानी बढ़ा रहा है तो मजनू का टीला की ओर से हनुमान सेतु की आने वालों की भी बड़ी समस्या जाम ही है।

भयंकर जाम लगता है

मंगलवार को हनुमान मंदिर के सामने दोनों ओर भयंकर जाम लगता ही है। इस जाम को कम करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, मगर सभी प्रयास असफल हुए हैं। हाल ही में यातायात पुलिस द्वारा हनुमान मंदिर सेतु के अंतिम छोर पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं। मगर इससे अभी बहुत सुधार नहीं दिख रहा है।

संस्था ने मुख्य सचिव को भेजे ये सुझाव

कश्मीरी गेट बस अड्डा परिसर से निकास ले रही बसों के निकास द्वार को वर्तमान रिंग रोड़ छोर से हटाकर जीटी करनाल रोड़ स्थित युधिष्ठिर सेतु के नीचे मध्य भाग के समक्ष खोला जाए। इस व्यवस्था में बसें जीटी करनाल रोड़ पर सीधे युधिष्ठिर सेतु के नीचे से निकलकर पातालेश्वर मंदिर के समीप रिंग रोड़ पर मर्ज होंगी।

कश्मीरी गेट बस अड्डे के विपरीत बस स्टैंड से निगम बोध घाट की ओर बढ़ते समय जो यू-टर्न वर्तमान समय में बसों के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है, उसे बंद कर सभी बसों को सलीमगढ़ बाइपास भेजकर यू-टर्न लेकर हनुमान मंदिर सेतु होते हुए बस अड्डे में प्रवेश करने का रूट दिया जाए।

वर्तमान यू-टर्न से मुड़कर बसें हनुमान मंदिर की ओर से आ रहे यातायात को काटकर बस अड्डे में प्रवेश करती हैं, जिससे यातायात प्रवाह बाधित रहता है। सलीमगढ़ बाइपास से बसें जब हनुमान मंदिर होते हुए आएंगी तो बाईं लेन में रहेंगी व बस अड्डा पहुंच कर बस अड्डे में प्रवेश कर लेंगी।

मोबाइल सेंट्रल वर्ज का उपयोग किया जाए। रिंग रोड पर सायं के समय युधिष्ठिर सेतु से चंदगी राम अखाड़ा के बीच सेंट्रल वर्ज को यमुना नदी की ओर एक लेन खिसका दिया जाए व सुबह, दोपहर के समय इसे मध्य से एक लेन विपरीत दिशा में खिसका दिया जाए।क्योंकि सामान्यतः सुबह दोपहर के समय मजनू का टीला से चंदगी राम अखाड़ा व कश्मीरी गेट बस अड्डा होते हुए निगम बोध घाट की ओर यातायात का दबाव अधिक रहता है।

वहीं, सायंकाल में हनुमान मंदिर से कश्मीरी गेट बस अड्डा व चंदगी राम अखाड़ा होते हुए मजनू का टीला की ओर यातायात का दबाव अधिक रहता है। सेंट्रल वर्ज को खिसका कर इस दबाव से आवश्यकतानुसार निजात पाई जा सकती है।चल (मोबाइल) सेंट्रल वर्ज इसका प्रभावी विकल्प है।इसके साथ ही चंदगी राम अखाड़ा ट्रैफिक सिग्नल को बैक टू बैक यू-टर्न व्यवस्था के अंतर्गत सिग्नल मुक्त कर निर्बाध यातायात आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

जेल में की दोस्ती, बाहर निकल कर्तव्य पथ पर वारदात करने की कोशिश; दो गिरफ्तार

कर्तव्य पथ (Kartavya Path) पर लूट और झपटमारी की वारदात को अंजाम देने की मंशा से घूम रहे दो बदमाशों रतन और बिजेन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से चोरी के दो दोपहिया वाहन और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि कर्तव्य पथ पर पुलिस 24 घंटे गंभीरता से गश्त करती है।

नई दिल्ली। कर्तव्य पथ (Kartavya Path) पर लूट और झपटमारी की वारदात को अंजाम देने की मंशा से घूम रहे दो बदमाशों रतन और बिजेन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से चोरी के दो दोपहिया वाहन और दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने बताया कि कर्तव्य पथ पर पुलिस 24 घंटे गंभीरता से गश्त करती है, क्योंकि वहां पर वीवीआईपी का राउंड लगता रहता है। हर एक कॉल को गंभीरता से लिया जाता है और वहां पर आने जाने वाले हर एक व्यक्ति पर निगाह रखी जाती है।

मांगे थे दस्तावेज

कर्तव्य पथ थाने में तैनात सिपाही संदीप और मोटरइसाइकिल पर गश्त करके संदिग्धों पर निगाह रखे हुए थे। उसी वक्त दोनों आरोपितों को मौके पर रोक कर मोटरसाइकिल के दस्तावेज मांगे। मोटरसाइकिल के दस्तावेज नहीं दिखाने पर दोनों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ करने पर आरोपितों ने मोटरसाइकिल विष्णु गार्डन, तिलक नगर से चोरी करने की बात बताई। उनकी निशानदेही पर दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से एक चोरी की स्कूटी जब्त की। उनके कब्जे से दो फोन भी जब्त किये। आरोपित रतन उर्फ रितिक उर्फ सूरज एक दर्जन वारदातों में शामिल रहा है।

जबकि बिजेन्द्र उर्फ गंजा हत्या की कोशिश और लूट की वारदात में शामिल रहा है। दोनों जेल में रहने के दौरान एक-दूसरे से मिले थे। आरोपित बिजेंदर मोटरसाइकिल चलाता था जबकि रतन पीछे बैठकर स्नैचिंग करता था।

मजबूत किलेबंदी करने से अब पुलिस परेशान, सिंघु बॉर्डर नहीं खुला; टीकरी, औचंदी और गाजीपुर सीमा खुली

किसानों के दिल्ली कूच करने के एलान के बाद 13 दिन पहले बंद किए गए सिंघु टीकरी औचंदी व गाजीपुर आदि मुख्य सीमाओं को खोलने का काम दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है लेकिन मजबूत किलेबंदी के कारण उन्हें सीमाओं को खोलने में परेशानी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण सिंघु सीमा (फ्लाई ओवर पर दोनों तरफ की मुख्य सड़कों) को पुलिस ने अभी खोलने का निर्णय नहीं लिया है।

नई दिल्ली। किसानों के दिल्ली कूच करने के एलान के बाद 13 दिन पहले बंद किए गए सिंघु, टीकरी, औचंदी व गाजीपुर आदि मुख्य सीमाओं को खोलने का काम दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है, लेकिन मजबूत किलेबंदी के कारण अब उन्हें सीमाओं को खोलने में परेशानी आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण सिंघु सीमा (फ्लाई ओवर पर दोनों तरफ की मुख्य सड़कों) को पुलिस ने अभी खोलने का निर्णय नहीं लिया है। यानी मुख्य सड़क मार्ग बंद ही रहेंगे। दोनों तरफ की सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा अभी जारी ही रहेगा। यहां फ्लाई ओवर के दोनों तरफ की सर्विस लेनों को दो दिनों से खोलने की कवायद जारी है। दोनों तरफ केवल एक-एक लेन खोलने की प्रक्रिया जारी है। रविवार देर रात तक यहां दोनों तरफ की सर्विस लेनों को नहीं खोला जा सका।

सर्विस रोड खोलने का काम दो दिन से जारी

दिल्ली से हरियाणा की ओर जाने वाली सर्विस रोड की एक लेन खोलने का काम दो दिनों से जारी है। हरियाणा से दिल्ली जाने वाली सर्विस रोड से काफी हद तक सामान हटा लिए गए हैं। दोनों तरफ की सर्विस लेनों से कई बैरिकेड तो हटा लिए गए अब एक मात्र जर्सी बैरियर बचा हुआ है। जर्सी बैरियर के बीच छह फीट कंक्रीट की दीवार बना देने के कारण अर्थ मूवर्स मशीन से उसे काटकर हटाने का काम जारी है।

सोमवार सुबह तक खुल जाएंगी लेनें

संभावना जताई जा रही है कि दोनों सर्विस लेनें सोमवार सुबह तक वाहन चालकों के लिए खोल दी जाएगी। यहां से पहले एक ही तरफ से पैदल यात्री आ जा पा रहे थे। अब उनकी आवाजाही दोनों तरफ से शुरू हो गई है। मौके पर बाहरी उत्तरी जिला के डीसीपी रवि कुमार सिंह दिनभर मौके पर मौजूद रहकर दोनों तरफ की सर्विस लेने खोलने की कवायद में जुटे रहे।

बैरिकेड्स पास में ही रहेंगे

गाजीपुर सीमा पर भी दोनों तरफ के मुख्य सड़क मार्ग खोल दिए गए। लेकिन सीमा पर रखे गए विभिन्न तरह के बैरिकेड्स जिन्हें अभी हटाकर साइड में रख दिए गए हैं, वे वहीं रखे रहेंगे। पुलिसकर्मियों की भी तैनाती 24 घंटे रहेगी। यहां की दोनों तरफ की सर्विस लेने अभी बंद ही रहेगी। सर्विस लेनों को नहीं खोला गया है।

टीकरी बॉर्डर खोला गया

उधर टीकरी सीमा को रविवार से खोल दिया गया। रास्ता खुलने से छोटे से लेकर बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। शनिवार को लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड हटाकर एक तरफ का रास्ता खोला गया था। रविवार को दोनों तरफ के रास्तों को पूरी तरह से खोल दिया गया, जिससे हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले वाहन चालकों को काफी राहत मिल रही है।

सीमा पर सुरक्षाकर्मी अभी भी तैनात ही हैं। सभी सीमाओं पर चौकसी व बैरिकेडिंग की तैयारी पहले की तरह ही रहेगी ताकि किसानों के दिल्ली की तरफ आने की सूचना मिलने पर मिनटों में सीमाओं को बंद किया जा सके।

फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी 2024 - फोरेंसिक जांच में चिकित्सकीय परिप्रेक्ष्य

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली : वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी और दंत चिकित्सा विभाग ने 24 फरवरी, 2024 को एक बेहद सफल सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम की मेजबानी की। फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बीच सहयोग पर, भारत भर के 35 मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के 200 प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया।

फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के तत्वावधान में आयोजित, सीएमई में वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों के नेतृत्व में ज्ञानवर्धक व्याख्यान और चर्चाएं हुईं।) दिल्ली, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (MAIDS) दिल्ली, और त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल।

कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए विविध विषयों में फोरेंसिक विश्लेषण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका, काटने के निशान की व्याख्या, चेहरे के पुनर्निर्माण की तकनीक और आपदा पीड़ित की पहचान में चुनौतियां और प्रगति शामिल हैं।

वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सर्वेश टंडन ने आपराधिक जांच और आपदा पीड़ित पहचान प्रक्रियाओं में फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया। सीएमई से प्राप्त सिफ़ारिशों ने फोरेंसिक विश्लेषण की सटीकता और दक्षता बढ़ाने के लिए फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। आपदा पीड़ित की पहचान में सुधार के लिए आपदा प्रतिक्रिया टीम में एक फोरेंसिक ओडोन्टोलॉजिस्ट को शामिल करना चाहिए।

सातों सीट हमें मिलीं तो दिल्ली को सुरक्षा कवच मिलेगा और सारे काम होंगे, फिर एलजी कोई काम नहीं रोक पाएंगे- सीएम केजरीवाल

तो दिल्लीवालों का 15 दिन के अंदर पानी का बिल हो जाएगा माफ, सीएम केजरीवाल ने लोगों से की ये अपील

पानी के गलत बिलों से राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रुक जाने को मुद्दा बनाकर अब आम आदमी पार्टी (AAP) इसे गर्मा रही है। आप इसे अब लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में उपयोग करने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसके संकेत भी दे दिए हैं।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। पानी के गलत बिलों से राहत देने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के रुक जाने को मुद्दा बनाकर अब आम आदमी पार्टी (AAP) इसे गर्मा रही है। आप इसे अब लोकसभा चुनाव में हथियार के रूप में उपयोग करने जा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को इसके संकेत भी दे दिए हैं।

सरकार द्वारा लाई जा रही इस स्कीम को रोकने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन में पूरी दिल्ली से आए लोगों ने सीएम केजरीवाल को अपने भारी-भरकम पानी के बिल दिखाए।

सीएम ने आश्वासन देते हुए कहा कि दिल्ली में सात लोकसभा की सीटें हैं। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि इस बार ये सातों सीट आईएनडीआई गठबंधन (INDI ALLIANCE) को दे दो और चुनाव जीतने के 15 दिन के अंदर सबका बिल माफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह स्कीम कैबिनेट में पास होनी है, लेकिन भाजपा ने एलजी से कहकर रुकवा दी है।

भाजपा वालों के सामने बिल जला देना

उन्होंने कहा कि भाजपा के सातों सांसद कभी दिल्ली की बात नहीं करते हैं। अगर ये सातों सीट हमें मिल जाएं तो दिल्ली को सुरक्षा कवच मिलेगा और सारे काम होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपके आसपास कोई भाजपा वाला रह रहा हो तो उसके घर की घंटी बजाना और उसके सामने ही पानी के गलत बिलों को जला देना।

गलत बिल वाले न भरें पानी का बिल

उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पानी का बिल गलत आया है, वो बिल न भरें। सीएम ने कहा कि दिल्ली में लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के गलत बिल आए हुए हैं। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉ. संदीप पाठक, दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय, कई मंत्री और पार्टी उपाध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

दिल्ली जल बोर्ड ने पास की स्कीम

सीएम ने कहा कि गत 13 जून को दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने यह स्कीम पास कर दी है। अब यह स्कीम कैबिनेट में पास करनी है, लेकिन भाजपा वालों ने एलजी से कहकर यह स्कीम रुकवा दी। अफसरों को भी धमकी दी गई है और वो रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी इतने वरिष्ठ आईएएस अफसरों को रोते हुए नहीं देखा।

भाजपा ने दिल्लीवालों को किया है दुखी

उन्होंने कहा कि अफसरों ने पूछने पर बताया कि हमें धमकी दी गई है कि अगर तुम यह स्कीम कैबिनेट में लेकर आए तो सस्पेंड कर देंगे। सीएम ने सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मेरा दिल जानता है कि कैसे मैं सरकार चला रहा हूं। उन्होंने कहा कि किस तरह से भाजपा और एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी किया है और किस तरह दिल्लीवालों का बेटा केजरीवाल ने उनकी सारी समस्याओं का समाधान किया।

उन्होंन कहा कि मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन मुझे पुरस्कार नहीं, आपका प्यार और भरोसा चाहिए। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अधिकारी चुने हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करें, लेकिन भाजपा ने कानून लाकर उसे रद्द कर दिया है।

विरोध-प्रदर्शन में आए लोगों ने भाजपा के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। जब सीएम अपना संबोधन खत्म कर वहां से चले गए तब लोगों ने भाजपा का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने अपने गलत पानी बिलों की प्रतियां भी जलाईं।

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आधे से ज्यादा मरीज यूपी और हरियाणा के, AAP ने भाजपा सरकारों पर लगाए गंभीर आरोप

आयुष्मान भारत योजना के मामले पर दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पलटवार किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल जमीनी हकीकत से अनजान हैं। दिल्ली के अस्पतालों में आधे मरीज भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों के होते हैं जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लागू है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएमजेएवाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के मामले पर दिल्ली सरकार उपराज्यपाल पलटवार किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल जमीनी हकीकत से अनजान हैं। दिल्ली के अस्पतालों में आधे मरीज भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों के होते हैं, जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) लागू है।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पीएमजेएवाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा कि हाल ही में कैग रिपोर्ट में योजना में अपात्र परिवारों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत करने की बात कही गई है। इन परिवारों ने योजना के तहत 0.12 लाख से 22.44 करोड़ रुपये तक का फायदा उठाया था।

एक ही मोबाइल नंबर से कई लोगों को मिल रहा लाभ

इस योजना के तहत एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया। एक मोबाइल नंबर पर तो 7.49 लाख लोगों को पंजीकृत करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि वह उपराज्यपाल को दिल्ली से सटे उतर प्रदेश के अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए आमंत्रित करते हैं। जहां योजना सिर्फ कागजों तक सिमट गई है।

यूपी-हरियाणा से मरीज पहुंच रहे दिल्ली

उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर से सटे दिल्ली के अस्पतालों में राष्ट्रीय राजधानी के मरीजों की संख्या उन पड़ोसी राज्यों के मरीजों के बराबर ही होती है। जीबी पंत अस्पताल में 50 प्रतिशत सर्जरी उन राज्यों के मरीजों की होती है, जहां आयुष्मान भारत योजना चालू है। निजी अस्पताल

सीजीएचएस (केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना) की दरों पर काम करना नहीं चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना के नियम ऐसे हैं कि दिल्ली के अधिकतर लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति के पास पक्की छत या दोपहिया वाहन हो। जबकि, दिल्ली सरकारी की दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत तीन लाख रुपये तक सालाना आय वाला व्यक्ति भी निजी अस्पतालों इलाज करा सकता है।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी और बकाया भुगतान की समस्या का जल्द सुलझाएं। ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। साथ ही स्वास्थ्य सचिव को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए अस्पताल निरीक्षण और बैठक में शामिल होकर इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

गाजियाबाद में कोरोना के 9 मरीज, संक्रमितों में दो बच्चे भी शामिल; स्वास्थ्य विभाग चिंतित

जिले में कोरोना के केस मिलने लगे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमण के सात नए मरीजों के मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का तनाव बढ़ गया है। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। बुजुर्ग संक्रमित को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि अन्य छह मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके बाद जनपद में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या नौ हो गई है।

गाजियाबाद। जिले में कोरोना के केस मिलने लगे हैं। शनिवार को कोरोना संक्रमण के सात नए मरीजों के मिलने पर स्वास्थ्य विभाग का तनाव बढ़ गया है। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं।

बुजुर्ग संक्रमित को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि अन्य छह मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके बाद जनपद में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या नौ हो गई है।

सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर ने बताया कि राजनगर में रहने वाले 53 वर्षीय व्यक्ति और उनके 26 वर्षीय बेटे को खांसी जुकाम था, जिसके चलते दोनों ने निजी लैब पर कोविड जांच करवाई थी। जांच में दोनों संक्रमित पाए गए।

इसके अलावा वैशाली में रहने वाले 23 वर्षीय युवक ने भी गले में खराश, जुकाम और बुखार के कारण कोविड जांच करवाई थी, वह भी संक्रमित पाया गया है। साहिबाबाद में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

वसुंधरा में रहने वाली एक महिला और उनके दो बच्चे कोराना संक्रमित पाए गए हैं। महिला के पति कुछ दिन पहले संक्रमित हुए थे और उनके संपर्क में आने से परिवार के तीन सदस्यों को भी संक्रमण हो गया।

एयरपोर्ट के डबल सोर्स बिजली लाइन के लिए 10.28 करोड़ जारी

परिवहन विशेष न्यूज

जेवर। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में बिजली की आपूर्ति के लिए शासन ने 10.28 करोड़ रुपये की राशि जिलाधिकारी को भेज दी है। अब तीनों प्राधिकरण राशि जारी कर यूपीपीसीएल को भेजेंगे। हवाई अड्डे के निर्माण से पहले अप्रैल के अंत तक विद्युत आपूर्ति की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। एयरपोर्ट के पूर्वी सब स्टेशन तक यीडा के सेक्टर-32 व सेक्टर-18 स्थिति 220 केवीए के सबस्टेशनों से आपूर्ति के लिए 27.43 करोड़ की लागत से लाइन तैयार की जाएगी।

हवाई अड्डे का निर्माण स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख करा रही है। कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की 100 प्रतिशत साझेदारी वाली है। जबकि सहयोगी कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) टाटा प्रोजेक्ट्स से प्रशासनिक भवन, टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे आदि बनवाने का काम करा रही है। एयरपोर्ट के रनवे, एटीएस टावर, टर्मिनल बिल्डिंग का काम बहुत जल्द पूरा करते हुए

ज्यूरिख की ओर से सितंबर 2024 में एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू कराने की तैयारी है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य से लेकर उसके संचालन, रखरखाव और सुरक्षा के लिए 24 घंटे बिना कटौती के विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है।

वाईआईएपीएल के सीईओ क्रिस्टॉफ शनेलमैन ने सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से एयरपोर्ट पर 19.5 मेगावाट व 93.5 मेगावाट क्षमता के दो कनेक्शन की मांग की थी। लाइन तैयार करने में होने वाले खर्च के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी। नागरिक उड्डयन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए 27.43 करोड़ की लागत से यीडा के सेक्टर-32 बीरमपुर व सेक्टर-18 मिर्जापुर स्थिति 220 केवीए के सबस्टेशनों से आपूर्ति देने के लिए डबल सोर्स की लाइन तैयार कराने का रास्ता साफ कर दिया है।

सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टेंडर का काम पूरा

220 केवीए के दोनों सबस्टेशनों से एयरपोर्ट के ईस्ट सब स्टेशन तक लाइनों के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टेंडर निकाला जा चुका है। ट्रांसमिशन विभाग जल्द दोनों लाइनों पर काम शुरू कराते हुए दो माह के भीतर एयरपोर्ट को विद्युत आपूर्ति कर दी जाएगी।

विशाल यादव, एसडीओ यूपीपीसीएल।

ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेस वे पर पलटा टेंपो, 10 से ज्यादा लोग घायल

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चलते हुए एक टेंपो पलट गया। 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब एक टेंपो आगरा से नोएडा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान नोएडा से करीब 25 किलोमीटर दूर एक तेज रफ्तार टेंपो सड़क पर अचानक पलट गया। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना थाना रबूपुरा क्षेत्र में हुई।

फूलों से बना राम मंदिर, अयोध्या की अलौकिकता की झांकी दिखी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। पुर रम्यता राम जब देखी। हरषे अनुज समेत बिसेषी।। बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना।। तुलसीदास ने रामचरितमानस में जनकपुरी की जिस अलौकिक शोभा का वर्णन किया है। उसका एक प्रतिरूप इन दिनों नोएडा स्टेडियम में लगी पुष्प प्रदर्शनी में भी दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रजातियों के फूलों से बनाया गया राम मंदिर शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण है।

वहीं हिरन, धनुष, ओम और श्रीराम की चरण पादुका भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। राम मंदिर की प्रदर्शनी लगाने वाली गाजियाबाद की शालिनी अग्रवाल बताती हैं कि इस मॉडल को 50 लोगों ने 10 दिन में तैयार किया है। इस बार राम मंदिर से अच्छा और विशेष किसी के लिए कुछ नही है। तो सोचा क्यों न इसके मॉडल को फूलों से प्रदर्शित किया जाए। वहीं, यहां लोग भी इसे देखने के लिए खासी संख्या में जुट रहे हैं। प्रदर्शनी में घरेलू कचरे को काले सोने (ऑर्गेनिक खाद) में बदलने की विधि भी समझाई जा रही है। बचपन से ही वातावरण व पौधों का प्रेम और महत्व समझाने के लिए स्कूली बच्चों को भी पौधरोपण सिखाया जा रहा है।

उद्यान प्रेमियों के लिए 60 से अधिक स्टॉल

पुष्प प्रदर्शनी में 60 से अधिक स्टॉल उद्यान प्रेमियों के लिए लगाई गई है। इसमें 35 नर्सरी हैं और कुछ तो कलिम्पोंग और भीमताल से आ रहे है। बीज, खाद, पौध, खेती के औजार, उद्यान का सजावटी सामान, कीटनाशक गमले हैं। विभिन्न वर्गों में लगभग 350 एन्ट्री हैं। मुख्य आकर्षण उद्यान व लैण्ड स्केपिंग प्रतियोगिता, सब्जियों पर नक्काशी कला है। वहीं, प्राधिरकरण के उद्यान विभाग द्वारा स्पॉट गार्डन श्रेणी में जैपेनिज गार्डन भी तैयार किया गया है। जो इस पुष्प प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण रहा।

सीईओ ने किया उद्घाटन

शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्टॉलों पर जाकर उनका निरीक्षण किया और कई फूलों की प्रजातियों को प्राधिकरण की नर्सरी में तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों से कहा। शाम के समय यहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक किया जा सकता है। इस वर्ष प्रदर्शनी की थीम स्टॉक पुष्प है।

3.39 करोड़ उधार लेकर वापस लौटाने के नाम पर 2.63 करोड़ रुपये हड़पे

गाजियाबाद। कविनगर क्षेत्र के राजनगर के रहने वाले राकेश कुमार त्यागी ने एक दंपती ने 2.63 करोड़ रुपये हड़प लिए। आरोप है कि अनुराग ने पहले अपने साथी राजीव के साथ मिलकर ठेकेदारी के नाम पर 3.39 करोड़ रुपये उधार लिए। इसके बाद इन्हें लौटाने के नाम पर अनुराग ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 43 बीघा जमीन का 8.20 करोड़ में सौदा करके 2.63 करोड़ रुपये हड़प लिए। जमीन का सौदा अनुराग ने फर्जी फर्द दिखाकर किया, जिसका पता बैनामा कराने के दौरान हुआ।

राकेश कुमार त्यागी का कहना है कि 2003 में उन्होंने अनुराग से बसंतपुर में जमीन खरीदी थी। तभी से उनकी जान पहचान है। अनुराग ने अपने साथी राजीव के साथ मिलकर पहले उनसे ठेकेदारी करने के लिए 10 लाख रुपये उधार लिए। जो तय समय में लौटा दिए। इसके बाद फिर अनुराग ने कई बार में 3.39 करोड़ रुपये लिए जो काफी समय तक नहीं लौटाए। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी भिजवाए तो अनुराग अपनी पत्नी के साथ उनके घर आया और कहा कि 3.39 करोड़ का आधा हिस्सा अनुराग और आधा हिस्सा राजीव देगा।

इसके बाद उनके बीच 1.69 करोड़ रुपये लौटाना का वादा हुआ लेकिन अनुराग ने उन्हें केवल 26 लाख रुपये लौटाए और बाकी 1.43 करोड़ के बदले उसने अपनी 43 बीघा जमीन का सौदा 8.20 करोड़ में किया।

इसमें से उन्होंने 1.43 करोड़ रुपये कम करके बैनामे के तौर पर 1.20 करोड़ रुपये दे दिए। अनुराग ने उन्हें जमीन की एक सत्यापित फर्द भी दी थी। बैनामा कराने के दौरान पता चला कि फर्द फर्जी है। अनुराग ने पत्नी के साथ मिलकर उनसे धोखाधड़ी कर और रकम ऐंठ ली। राकेश का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर अनुराग और मृदुला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसीपी कविनगर अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है।

हिंदी-अंग्रेजी का झगड़ा अब बेमानी

यह लोगों के बीच का भाषिक संवाद बदलने का एक नमूना है। इसके और भी पक्ष हैं। जब हम ऑक्सफोर्ड और वेब्स्टर के शब्दकोशों में सही वर्तनी और हिज्जे ढूंढ रहे होते हैं, तब इंटरनेट पर भेजे जा रहे संदेशों में उन शब्दों के संक्षिप्त रूपों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा होता है।

लेखक: बाल मुकुंद

जिस तरह देश की विविध अनुसूचित भाषाओं के लोग यह सोचते हैं कि हिंदी की वजह से उनकी भाषा का प्रभाव कम हो रहा है, उसी तरह हिंदी सेवियों की एक बड़ी तादाद ऐसा मानती है कि अंग्रेजी के कारण हिंदी का प्रसार बाधित हो रहा है। लेकिन खुद अंग्रेजी का क्या हाल है? जब हम एक पूर्ण और सशक्त भाषा की बात सोचते हैं, तो हमारे जेहन में उसके कुछ निश्चित प्रतिमान उभरते हैं। जैसे, उसकी एक विकसित लिपि होगी, ध्वनि संसार होगा, शब्दों का विशाल भंडार होगा। शब्दों की वर्तनी, उनका उच्चारण और अर्थ सुनिश्चित होगा। व्याकरण होगा। उसका अपना साहित्य होगा, जिसे पढ़ने वाले लोग होंगे। और उसे सत्ता (आर्थिक-राजनीतिक) का समर्थन प्राप्त होगा। क्या इन पारंपरिक मानकों पर आज की कोई भी भाषा दावे से खरी उतरती है?

इमोजी का बोलबाला

अंग्रेजी का प्रयोग करने वाली नई पीढ़ी बहुत तेजी से इमोजी की तरफ बढ़ रही है। कोई बात अच्छी लगे तो एक पूरा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। किसी बात की आलोचना करनी हो और इस तरह से करनी हो कि दूसरा पक्ष आहत न हो, तो उसके लिए कोई अच्छा शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि इमोजी से पूरे प्रेम पत्र लिखे जा सकते हैं। हम भाषा के संदर्भ में आर्थिक प्रभुत्व की चर्चा करते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबारों और उत्पादों के साथ भी इमोजी इस्तेमाल होने लगे हैं। ऐपल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ट्विटर, फेसबुक, एलजी, एचटीसी, बर्गर किंग और पेप्सीको जैसी तमाम कंपनियां इमोजी इस्तेमाल कर रही हैं, और उनके साथ उनके ग्राहक भी।

उनके बीच एक नई भाषा विकसित हो रही है। यानी रोमन लिपि और शब्दों की सही वर्तनी का महत्व खत्म! जब भी कोई नई भाषा विकसित होती है, वह पारंपरिक भाषाओं का दायरा संकुचित करती है। समाज में ऐसे कई तरह के छोटे-मोटे संकेत विकसित होते हैं जो समय के साथ प्रचलन से बाहर हो जाते हैं- यह सोच कर हम इमोजी की भाषा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह लोगों के बीच का भाषिक संवाद बदलने का एक नमूना है। इसके और भी पक्ष हैं। जब हम ऑक्सफोर्ड और वेब्स्टर के शब्दकोशों में सही वर्तनी और हिज्जे ढूंढ रहे होते हैं, तब इंटरनेट पर भेजे जा रहे संदेशों में उन शब्दों के संक्षिप्त रूपों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा होता है। वहां सिर्फ 'आय लव यू' के लिए इलू (आयएलयू) और 'फियर ऑफ मिसिंग यू के लिए फोमू' (एफओएमयू) ही नहीं बन रहा है, एक पूरी शब्दावली विकसित हो रही है, जिसमें बीटुबी (बिजनेस टु बिजनेस), केपीआई (की-परफॉर्मेंस इंडीकेटर), सीपीएम (कॉस्ट पर थाउजैंड) और यूजीसी (यूजर जेनरेटेड कॉन्टेंट) जैसे प्रयोग भी शामिल हैं। ये नए संक्षिप्त शब्द पहले के अनेक शब्दों से बने पूरे फ्रेज को विस्थापित कर देते हैं।

आज सिर्फ दोस्तों की अनौपचारिक मंडली में ही नहीं, कॉर्पोरेट की औपचारिक चिट्ठियों, व्यापारिक पत्राचार और तकनीक की दुनिया में भी इस भाषा में लिखित संवाद हो रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में इन संक्षिप्त रूपों को मान्यता प्राप्त है। इनमें से यदि कोई नवनिर्मित शब्द समझ में न आए तो उसे गूगल कर आसानी से देखा जा सकता है। आज से चार-पांच दशक बाद वाली पीढ़ी के लिए शायद यह जान पाना भी मुश्किल हो कि फोमू किन-किन शब्दों के संक्षेपीकरण से बना है। उसके लिए फोमू ही वह शब्द होगा, जिसके माध्यम से वह अपनी बात कहेगी। फेसबुक पर हर मिनट 50 लाख से ज्यादा लोग अपनी टिप्पणियां पोस्ट करते हैं और 30 लाख से ज्यादा लोग अपना स्टेटस अपडेट करते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रति मिनट करोड़ों की तादाद में पोस्ट किए जाते हैं और मोबाइल से पचास लाख से ज्यादा ट्वीट भेजे जाते हैं। इसी एक मिनट में इंटरनेट की दुनिया में डेढ़ लाख से ज्यादा टेक्स्ट का आदान-प्रदान होता है। हिंग्लिश और चिंग्लिश जैसे नए भाषा रूपों ने अंग्रेजी के व्याकरण की अनिवार्यता को काफी संकुचित कर दिया है। यहां तक कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे बाल्टिक देशों के लोग भी अपनी भाषाओं के दायरे से बाहर निकल कर जब कभी टूटी-फूटी अंग्रेजी में संवाद करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर वह व्याकरण के नियमों से परे ही होती है। हां, लिपि जरूर रोमन बनी हुई है। नई पीढ़ी तक अंग्रेजी की अपनी वर्तनी बचाने के लिए शिक्षक, संस्थाएं और सरकारें जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, बहामा, जमैका, गुयाना, दक्षिणी अफ्रीका, यहां तक कि एशियाई देशों में भी युवा छात्रों के लिए स्पेलिंग और हिज्जे की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ट्रॉफियां दी जा रही हैं। लेकिन शब्दकोश, व्याकरण की पढ़ाई और भाषा संरक्षण के तमाम उपायों के बावजूद अंग्रेजी अपने को संभाल नहीं पा रही है।

बदलता हुआ रूप

टेक्नॉलजी और वैश्वीकरण ने आज की सभी भाषाओं की जड़ें हिला दी हैं। भाषाओं के पारंपरिक ढांचे दरकते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन में युवा छात्रों द्वारा अंग्रेजी शब्दों की सही वर्तनी की उपेक्षा और हिंदुस्तान में निरक्षरों द्वारा अपने मोबाइल फोन पर आए कॉलर नंबर को उनकी आकृति या विशिष्ट रिंग टोन से पहचानने की प्रवृत्ति को अभी तक हम दो अलग-अलग स्थानीय सामुदायिक व्यवहारों की तरह देख रहे हैं। शायद हम इन दोनों के बीच के संबंध को पहचान नहीं पा रहे। ये वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से अपना साम्राज्य बढ़ा रही अंग्रेजी भाषा के मानक रूप के क्षरण के कुछ उदाहरण हैं। लेकिन हमारे भाषाई व्यवहार में ऐसे और भी कई संकेत देखने को मिल रहे हैं। भाषाएं मरती नहीं, वे अपना रूप बदलती हैं, कुछ अवशेषों के साथ। अंग्रेजी भी अपनी लिपि और कुछ ध्वनियों के साथ दूसरी भाषाओं की तुलना में शायद कुछ ज्यादा लंबे समय तक बनी रहे, लेकिन वह अंग्रेजी यह अंग्रेजी नहीं होगी।

सीएम योगी के दिल्ली जाने के दौरान पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कौशांबी। यूपी गेट फ्लाईओवर पर शनिवार को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 की लेन पर यातायात सामान्य रहा। दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरफोर्स से एलिवेटेड होते हुए दिल्ली गये। इस बीच पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे। काफिला गुजरने के दौरान यातायात को कुछ देर के लिए रोका गया था।

डीसीपी निमिष पाटिल का कहना है कि यूपी गेट पर किसानों के आने की संभावना पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। सुबह में एनएच-9 और डीएमई पर जाम की स्थिति नहीं रही। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए। वहीं, हिंडन एयरफोर्स, करहेड़ा और इंदिरापुरम, कौशांबी थाना क्षेत्र के यूपी गेट व एनएच- 9 पर जगह-जगह पुलिस कर्मियों की डयूटी लगाई गई थी। उन्होंने सभी को सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत दी। कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम का काफिला दिल्ली भेजा गया। उधर, देर शाम तक यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर लगा बैरिकेड नहीं हटाया गया। हालांकि, हरियाणा और दिल्ली के शंभू व सिंघु बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग को हटाने की खबर के बाद वैशाली-वसुंधरा, कौशांबी व इंदिरापुरम के लाखों लोग यूपी गेट-गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस लेन से बैरिकेड हटाकर रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काफिले समेत शाम साढ़े छह बजे दिल्ली से यूपी गेट होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो गये।

Royal Enfield Scram 650 और Classic 650 लॉन्च से पहले हुई स्पॉट, जानिए क्या होंगे फीचर्स

Royal Enfield Scram 650 और Classic 650 को लॉन्च से पहले परीक्षण के दौरान देखा गया है। जहां आगामी बाइक्स के हल्के-फुल्के डिजाइन की झलक देखने को मिली है। रॉयल एनफील्ड इस साल में तीन नई बाइक पोर्टफोलियो में जोड़ने की प्लानिंग कर रही हैं। जिनमें ये दो बाइक प्रमुख तौर पर शामिल हैं। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड लगातार अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। हाल ही में कंपनी की दो अपकमिंग बाइक्स को लॉन्च से पहले परीक्षण के दौरान देखा गया है। इसमें स्क्रैम 650 और क्लासिक 650 का नाम शामिल है। आइए इनके बारे में जान लेते हैं।

Scram 650 और Classic 650 हुई स्पॉट

परीक्षण के दौरान सामने आई तस्वीरों से आगामी बाइक्स का समग्र डिजाइन पता चलता है। उम्मीद है कि कंपनी आने वाली स्क्रैम 650 को इंटरसेप्टर बियर 650 नेमप्लेट के तहत पेश करेगी। हालाँकि आरई ने अभी तक इसके बारे में कोई संबंधित विवरण साझा नहीं किया है। इसके बारे में आने वाले दिनों में ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है।

परीक्षण के दौरान दिखी तस्वीरों से इनकी डिजाइन पता चलती है। क्लासिक 650 काफी हद तक लंबी क्लासिक 350 जैसा दिखती है, जबकि स्क्रैम 650 स्टेरॉयड पर इंटरसेप्टर 650 जैसा दिखता है। लॉन्च होने पर स्क्रैम 650 को इंटरसेप्टर बियर 650 नाम मिलने की संभावना है।

फीचर्स (संभावित)

इन अपकमिंग बाइक्स के कुछ फीचर्स की जानकारी भी सामने आई है। कहा गया है कि स्कैम 650 में सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। राउंड शेप में हेडलाइट सेटअप जो साइड में स्लीक इंडीकेटर्स द्वारा समर्थित होगा। इसमें स्टाइलिश स्पोक व्हील दिए जा सकते हैं।

वहीं, क्लासिक 650 को लेकर उम्मीदें हैं कि इसकी रूपरेखा Super Meteor 650 से मिलती-जुलती होगी। ध्यान दें ये सिर्फ अफवाहें हैं। कंपनी के द्वारा दोनों ही बाइक्स को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है।

इलेक्ट्रिक सेगमेंट में टाटा का दबदबा, जानिए दूसरी कंपनियों की कैसी रही स्थिति

जनवरी 2024 में भारतीय बाजार में कुल 8164 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं हैं। जबकि दिसंबर 2023 में 3447 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। EV सेगमेंट में सालाना आधार पर 13.07 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 7220 यूनिट्स की सेल हुई थी। जनवरी 2024 में टाटा मोटर्स ने 5591 यूनिट्स के साथ सबसे अधिक ईवी बेची हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि इसमें ऑटो निर्माता भी जमकर वाहन लॉन्च कर रहे हैं। वर्तमान समय में ईवी सेगमेंट में कई कंपनियों के पास अच्छा पोर्टफोलियो है। यहां जनवरी 2024 में सेल हुई ईवी के बारे में बताने वाले हैं। जनवरी 2024 में टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों की अच्छी खरीदारी हुई है।

EV की बिक्री में टाटा की अच्छी स्थिति

जनवरी 2024 में भारतीय बाजार में कुल 8,164 इलेक्ट्रिक कारें बेची गईं हैं। जबकि दिसंबर 2023 में 3,447 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। ईवी सेगमेंट में सालाना आधार पर 13.07 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 7,220 यूनिट्स की सेल हुई थी। जनवरी 2024 में टाटा मोटर्स ने 5,591 यूनिट्स के साथ सबसे अधिक ईवी बेची हैं। बिक्री के मामले में अन्य ऑटो निर्माता टाटा से काफी पीछे हैं।

महिंद्रा-MG ने कितने यूनिट बेची

इस महीने में महिंद्रा 1162 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही है। वहीं, तीसरे पर एमजी मोटर्स का नाम शामिल है जिसने 742 यूनिट बेची हैं। हुंडई ने भारतीय ईवी बाजार में जनवरी 2024 के दौरान 162 यूनिट्स की बिक्री की है।

सभी कंपनियों की बिक्री का आंकड़ा

कंपनी	ईवी बिक्री
टाटा मोटर्स	5591 यूनिट
एमजी	1162 यूनिट
महिंद्रा	741 यूनिट
हुंडई	162 यूनिट
BYD	150 यूनिट

पैसेंजर्स व्हीकल की बिक्री में आ सकती है कमी, ईवी सेगमेंट में ग्रोथ की संभावना-

अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में ग्राहक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आने वाले वाहनों को कम तरजीह देंगे। साथ ही कहा गया है कि इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा जारी रह सकता है। टाटा मोटर्स यात्री वाहन के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि इस दौरान ईवी के बुनियादी ढांचे के मजबूत होने की भी संभावना है।

नई दिल्ली। अगले वित्त वर्ष में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री कम रहने का अनुमान लगाया गया है। टाटा मोटर्स के द्वारा कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में 5 प्रतिशत तक बिक्री कम रहने की संभावना है। अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में ग्राहक इस सेगमेंट में आने वाले वाहनों को कम तरजीह देंगे।

साथ ही कहा गया है कि इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा जारी रह सकता है। आइए इस खबर के बारे में जान लेते हैं।

वित्त वर्ष में कम होगी PV की बिक्री

टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में पैसेंजर व्हीकल (Passenger Vehicle) की बिक्री में कमी आएगी। यह सेगमेंट धीमा रहेगा। इन्होंने कहा कि इस सेगमेंट में भले ही कमी देखने को मिलेगी। लेकिन तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में इजाफा होने की उम्मीद है। इन्होंने ईवी के बुनियादी ढांचे के मजबूत होने की संभावना जताई है।

पैसेंजर व्हीकल के लिए रहेगी चुनौती

चंद्रा ने कहा कि वित्त वर्ष 2013 में उद्योग में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 25 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो इस वित्तीय वर्ष में मध्यम होकर लगभग 8 प्रतिशत होने की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में फिलहाल हाई बेस इफेक्ट देखने को मिल रहा है और अगले वित्त वर्ष में इस सेगमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति रह सकती है।

शैलेश चंद्रा ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के वाहनों की कीमतों को बढ़ने को लेकर भी संकेत दिया है। इन्होंने कहा कि कच्चे तेल की लागत बढ़ रही है जिसका यात्री वाहनों की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

ईवी सेगमेंट में जारी रहेगी बढ़ोत्तरी

वर्तमान समय में ग्राहक ईवी वाहनों की तरफ अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। ऐसे में अगले वित्त वर्ष में सेगमेंट के वाहनों की बिक्री में इजाफा होने का अनुमान है।

सुजुकी ने 2-व्हीलर इंडस्ट्री में भी बनाया रिकॉर्ड, पार किया 10 लाख यूनिट सेल का आंकड़ा

कंपनी की पॉपुलर टू-व्हीलर Suzuki Access 10 लाखवीं यूनिट थी। इसे एसएमआईपीएल के गुरुग्राम स्थित खेरकी धौला प्लांट से तैयार किया गया। फरवरी 2006 में अपनी स्थापना के बाद से एसएमआईपीएल ने उद्योग में अपनी उपस्थिति बढ़ाना और विस्तार करना जारी रखा है। वर्तमान में कंपनी Suzuki V-Strom 800 DE को पेश करने पर काम कर रही है। इसे हाल ही में हुए एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था।

नई दिल्ली। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने घरेलू बाजार में नया माइलस्टोन हासिल किया है। कंपनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय बाजार के अंदर उसकी 10 लाख टू-व्हीलर सेल हुई हैं। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

Suzuki Access बनी 10 लाखवीं यूनिट

कंपनी की पॉपुलर टू-व्हीलर Suzuki Access 10 लाखवीं यूनिट थी। इसे एसएमआईपीएल के गुरुग्राम स्थित खेरकी धौला प्लांट से तैयार किया गया। फरवरी 2006 में अपनी स्थापना के बाद से, एसएमआईपीएल ने उद्योग में अपनी उपस्थिति बढ़ाना और विस्तार करना जारी रखा है। कंपनी का कहना है कि ये उपलब्धि राइडर्स बेहतरीन सर्विस देने के परिणामस्वरूप हासिल हुई है।

इस महत्वपूर्ण माइलस्टोन तक पहुंचने पर अपना आभार व्यक्त करते हुए कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष, रजनीश कुमार मेहता ने कहा-

एक साल से भी कम समय में दस लाख यूनिट का उत्पादन हासिल करना सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। घरेलू बाजार और हमारे विदेशी बाजारों से सुजुकी टू-व्हीलर्स की लगातार बढ़ती मांग को बनाए रखने के लिए, हम प्रति वर्ष 1 मिलियन यूनिट की अपनी मूल स्थापित क्षमता से आगे निकल गए हैं।

Suzuki V-Strom 800 DE की तैयारी

वर्तमान में कंपनी Suzuki V-Strom 800 DE को पेश करने पर काम कर रही है। इसे हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। सुजुकी की ओर से नए 776 सीसी, पैरेलल-ट्विन इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जो लिक्विड-कूल्ड है। ये इंजन 8,500 आरपीएम पर 83 बीएचपी की अधिकतम पावर और 78 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। ऑन ड्यूटी गियरबॉक्स एक 6-स्पीड यूनिट है, जिसे बाई-डायरेक्शनल

बिगड़ती कानून व्यवस्था का खामियाजा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ रहा है

प्रह्लाद सबनानी

पश्चिम बंगाल के विशेष इलाके संदेशखाली में घटित उक्त घटनाओं का वर्णन केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। वरना, पूरे पश्चिम बंगाल में ही आज अराजकता का माहौल है जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति को विपरीत रूप में प्रभावित कर रहा है।

किसी भी देश में आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए उस देश में सामाजिक शांति बनाए रखना अति आवश्यक है। यही शर्त किसी भी राज्य की आर्थिक प्रगति के सम्बंध में भी लागू होती है। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य कुछ वर्ष पूर्व तक भारत में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति कर रहे राज्यों के बीच अग्रिम पंक्ति में रहता आया है। परंतु, हाल ही के वर्षों में पश्चिम बंगाल में शांति भंग होती दिखाई दे रही है, इसका प्रभाव स्पष्टतः इस राज्य के आर्थिक विकास पर भी विपरीत रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों से पश्चिम बंगाल में सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न होता दिखाई दे रहा है। पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बन गया है, विशेष रूप से सनातन संस्कृति का पालन करने वाले बंगाल के शांति प्रिय नागरिकों पर असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हाल ही के समय में पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों जैसे संदेशखाली इलाके में महिलाओं पर अत्याचार आम बात हो गई है।

संदेशखाली, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का एक छोटा कस्बा है। यह बांग्लादेश की सीमा से सटा सीमावर्ती क्षेत्र भी है, जहां हिंदू अनुसूचित जातियों की आबादी बहुलता में है। संदेशखाली, पश्चिम बंगाल की उन 14 विधानसभा की सीटों में शामिल हैं जोकि भारत बांग्लादेश सीमा से सटीं हुई हैं। दुर्भाग्य से संदेशखाली सहित यह सभी विधानसभा सीटें अतिवादी संगठनों द्वारा समर्थित सुनियोजित षड्यंत्र का एक हिस्सा बन गई हैं। इन 14 सीमावर्ती विधान सभा क्षेत्रों में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। यहां की जनसांख्यिकी बदलने की साजिश का षड्यंत्र भी उच्च स्तर पर हो रहा है। वास्तव में, यह क्षेत्र पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी ISI की आतंकी गतिविधियों के अलावा तमाम आपराधिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। कुछ समय पहले तक संदेशखाली में मुस्लिम जनसंख्या नहीं के बराबर थी, लेकिन अवैध घुसपैठ के चलते यहां असामाजिक तत्वों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह इलाका जनसांख्यिकी परिवर्तन की चपेट में आ गया है। इसमें सबसे बड़ी आबादी अब रोहिगियाई मुसलमानों की हो गई है।

गौर करने वाली बात है कि विगत चुनावों के दौरान घटित सभी आपराधिक घटनाओं में अधिकतर अपराधी असामाजिक तत्व मुस्लमान ही पाए गए थे। यह मामले गौ-तस्करी से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े रहे हैं। इस तरह के सभी गैरकानूनी मामलों में मुस्लिम ही अभियुक्त पाए जाते हैं। संदेशखाली में जो कुछ सामने आया है अथवा आ रहा है, यह कोई पहली बार घटित हुई वारदातें नहीं है। हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप की एक नहीं बल्कि सैंकड़ों घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जब भी आवाज उठायी है तो परिणाम में उन्हें ही निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। न सिर्फ संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है बल्कि उनके घरों को भी जला दिया गया है। इस क्षेत्र में हिंदू अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं नाबालिग़ लड़कियों को इस इलाके के दबंग घुसपैठिए अपनी हवस का शिकार बनाने के उद्देश्य से जबरन उठा ले जाते हैं। इस क्षेत्र में तस्करी, मादक पदार्थ, हथियार, गोमांस आदि अपराधों में संलिप्त शेख शहंशाह जैसे मुस्लिम दबंगों का बोलबाला है। हाल ही में शेख शहंशाह के ठिकानों पर छापेमारी के लिए गई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर उसके गुर्गों द्वारा हिंसक हमला भी किया गया था। इस हमले में ED के कई अधिकारी गम्भीर रूप से घायल हुए थे। इस इलाके में नौकरी/रोजगार, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने की आड़ में भी अनेक महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।

पश्चिम बंगाल के विशेष इलाके संदेशखाली में घटित उक्त घटनाओं का वर्णन केवल उदाहरण के तौर पर किया गया है। वरना, पूरे पश्चिम बंगाल में ही आज अराजकता का माहौल है जो पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति को विपरीत रूप में प्रभावित कर रहा है।

लगभग 1960 के दशक तक पश्चिमी बंगाल की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय से अधिक हुआ करती थी। पश्चिम बंगाल, भारत के प्रथम तीन सबसे अधिक धनी राज्यों में शामिल था। पहले दो राज्य थे- महाराष्ट्र एवं गुजरात। 1980 का दशक आते आते पश्चिम बंगाल की औसत प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय के लगभग बराबर तक नीचे आ गई थी। 1990 के दशक में राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल की तुलना में तेज गति से आगे बढ़ने लगी और पश्चिम बंगाल का स्थान देश में 7वें स्थान पर आ गया। वर्ष 2000 में और भी नीचे गिरकर 10वें स्थान पर आ गया एवं वर्ष 2011 में यह 11वें स्थान पर आ गया। यह गिरावट आज भी जारी है और आज पश्चिम बंगाल औसत प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 14वें स्थान पर आ गया है।

इसी प्रकार, वर्ष 1993-94 एवं 1999-2000 के बीच पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की गई थी जबकि भारत का राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 4.6 प्रतिशत था। अगली दशाब्दी में पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर गिरकर 4.9 प्रतिशत रह गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत बढ़कर 5.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2019-20 के दौरान पश्चिम बंगाल में औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर और भी नीचे गिरकर 4.2 प्रतिशत हो गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत 5.2 प्रतिशत रहा। इस प्रकार पश्चिम बंगाल एवं राष्ट्रीय स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में यह अंतर और भी बढ़ता ही जा रहा है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल में विकास दर राष्ट्रीय स्तर पर औसत विकास दर से अधिक थी। परंतु, वामपंथी दलों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में विकास दर राष्ट्रीय औसत से कम हो गई थी। पश्चिम बंगाल पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लगातार कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है। विशेष रूप से वामपंथी दलों एवं तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल के दौरान पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगति विपरीत रूप से प्रभावित होती रही है।

वर्ष 2022 में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 157,254 रुपए था जबकि विश्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का राष्ट्रीय औसत 2411 अमेरिकी डॉलर था। यदि 80 रुपए प्रति डॉलर की दर पर अमेरिकी डॉलर को रुपए में बदला जाए तो यह राशि लगभग 164,000 रुपए प्रति व्यक्ति रहती है, जो पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति औसत से कहीं अधिक है। जबकि पश्चिम बंगाल किसी समय पर भारत के समस्त राज्यों के बीच सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ राज्य रहा है। यह देश की आर्थिक राजधानी भी माना जाता रहा है। आज आर्थिक प्रगति के मामले में पश्चिम बंगाल की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती जा रही है। यह सब पश्चिम बंगाल में छिन्न-भिन्न हो रहे सामाजिक ताने बाने के चलते एवं उपरोक्त वर्णित संदेशखाली जैसी घटनाओं में हो रही वृद्धि के चलते हो रहा है।

संपादक की कलम से

जरूरी है बेल कानून

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जमानत के प्रावधानों से संबंधित नया कानून बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत को पुलिस स्टेट नहीं बनाना चाहिए और लोकतंत्र की जड़ें गहरी होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से यह पूछना मायने रखता है कि जमानत के प्रावधानों से संबंधित नया कानून लाने पर काम हो रहा है या नहीं। दरअसल, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के ही जुलाई 2022 में दिए एक आदेश से जुड़ा है। उसमें कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि जिन मामलों में अधिकतम सजा सात साल से कम हो, उनमें जमानत को लेकर नया कानून बनाया जाए।

पुलिस स्टेट न बने : इस संबंध में जो कोर्ट की चिंता है, वह देश के सिविल सोसाइटी सदस्यों की बातों से भी लंबे समय से झलकती रही है। जुलाई 2022 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उसे इन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया था कि भारत को कभी पुलिस स्टेट में तब्दील नहीं होना चाहिए।

शक्ति का दुरुपयोग : इसे लेकर हमेशा सचेत रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि आजादी के बाद से भारत लोकतंत्र की राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा है। अगर थोड़ा आगे-पीछे आजाद हुए अन्य देशों के अनुभवों के मुकाबले देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं। लेकिन फिर भी पुलिसिया ताकतों के गैरजरूरी इस्तेमाल की शिकायतें मिलती रहती हैं। और, दुर्भाग्य से उनमें से ज्यादातर शिकायतें ऐसी होती हैं, जिन्हें निराधार कहकर खारिज नहीं किया जा सकता।

दलगत स्वरूप नहीं : यहां इस तथ्य को रेखांकित करना खास तौर पर जरूरी है कि यह समस्या किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस अर्थ में अच्छा था कि तब समस्या का समाधान अपेक्षाकृत आसान होता। लेकिन अलग-अलग कालखंडों की बात तो दूर, एक ही समय में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकार होने के बावजूद वहां से ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं।

कानून की जरूरत : शायद यह भी एक वजह है कि अदालतों ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के ऐसे कई आदेश हैं जो बताते हैं कि सरकारी तंत्र को नागरिकों के अधिकारों को लेकर ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। अनावश्यक गिरफ्तारी या जमानत में देरी के अलग-अलग मामलों से निपटते हुए ऊपरी अदालतें ऐसे निर्देश देती रही हैं। लेकिन उनका ज्यादा असर नहीं दिखा तो उसकी एक वजह यह भी है कि इस बारे में कोई ऐसा स्पष्ट कानून नहीं है, जो राज्यों में कानूनी एजेंसियों के लिए मार्गदर्शन का काम करे।

टालमटोल न हो : जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट का यह दखल जरूरी और महत्वपूर्ण है। अगर सरकार ने अब तक कानून बनाने की दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं की है तो अपने इस रुख को तत्काल बदलते हुए प्रभावी कानून लाने के प्रयासों में तेजी लानी चाहिए।

ज्ञान

भावनाओं की राजनीति

कर्नाटक सरकार ऐसा कानून बना रही है जिसमें हर कंपनी को नोटिस बोर्ड पर ये बताना होगा कि उसके यहां कितने कन्नड़ कर्मचारी काम करते हैं। जो कंपनियां इन नियमों को नहीं मानेंगी उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कर्नाटक सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनियों को नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से अपने कन्नडिगा कर्मचारियों की संख्या प्रदर्शित करनी होगी। इस खबर ने कई हलकों में ठीक ही चिंता पैदा की है।

विधानसभा में चर्चा : प्रस्तावित कानून की गंभीरता तो अपनी जगह है ही, ध्यान देने लायक बात यह भी है कि इसकी जानकारी सबसे पहले विधानसभा में एक और बिल पर चर्चा के दौरान सामने आई। वह बिल जो 15 फरवरी को पारित किया जा चुका है, व्यवसायों के लिए 60 फीसदी साइनबोर्ड कन्नड भाषा में रखना अनिवार्य बनाता है। दूसरी बात यह भी बताई गई है कि सरकार 'कन्नडा कवालू' नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली है, जो नागरिकों के लिए भाषाई भेदभाव की शिकायत करना आसान बनाएगा।

भाषाई संकीर्णता : इन तमाम कदमों को समग्रता में देखें तो साफ है कि ये भाषाई भावनाओं पर आधारित संकीर्ण राजनीति को बढ़ावा देने वाले हैं। इस तरह की राजनीति किसी पार्टी को खास इलाके में थोड़े समय के लिए लोकप्रियता भले दे दे, लंबे समय में किसी का भला नहीं कर पाती। महाराष्ट्र से लेकर असम तक अतीत के अनुभवों से इसकी पुष्टि होती है।

निवेश पर आंच : निश्चित रूप से लगभग हर प्रदेश और क्षेत्र में स्थानीय युवाओं की बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा है। लेकिन इसका हल क्षेत्र और भाषा के आधार पर स्थानीय भावनाओं को भड़काने में नहीं है, न ही देश के दूसरे हिस्से से आ रहे लोगों के खिलाफ माहौल बनाने में है। बल्कि, इससे बाहर से निवेश और टैलंट आने का सिलसिला बंद होने का खतरा है, जिससे उस राज्य की विकास संभावनाएं ही नहीं, रोजगार के मौके भी प्रभावित हो सकते हैं।

अन्य राज्यों का हाल : यह बात सही है कि हाल के वर्षों में बेरोजगारी के मुद्दे को स्थानीय संदर्भों में देखने की प्रवृत्ति तेज हुई है। कई राज्य सरकारों ने स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में रिजर्वेशन की घोषणा की थी। मिसाल के तौर पर हरियाणा (75 फीसदी), महाराष्ट्र (80 फीसदी तक), आंध्र प्रदेश (75 फीसदी) और मध्य प्रदेश (70 फीसदी) के नाम लिए जा सकते हैं।

कोर्ट में मामले : लेकिन किसी तुलना में जाने से पहले दो बातों पर गौर करने की जरूरत है। पहली तो यह कि स्थानीय आरक्षण से जुड़े इन ज्यादातर मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। ये मामले चल रहे हैं और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इन्हें खारिज कर दे। दूसरी बात यह कि कर्नाटक में मामला स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके मुहैया कराने भर का नहीं लगता। जिस तरह से ये कदम उठाए और प्रचारित किए जा रहे हैं, उससे भाषाई भावनाओं के भड़कने का साफ खतरा है। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार इन खतरों को लेकर सचेत होगी और हालात को उस तरफ नहीं जाने देगी।

इलेक्टोरल बांड के खिलाफ अपनी लड़ाई को जगदीप छोकर ने अंजाम तक पहुँचाया

जगदीप छोकर ने कहा कि अदालत के फैसले को मैं 'देर आए दुरुस्त आए' ही कहूंगा। क्योंकि निर्णय कुछ महीनों से कोर्ट में रिजर्व था। जिसे काफी पहले सुनाया जाना चाहिए था। निर्णय को दो भागों में लिखा गया। पहले निर्णय को चार जजों ने और दूसरे निर्णय को एक अन्य जज ने लिखा।

डॉ. रमेश ठाकुर

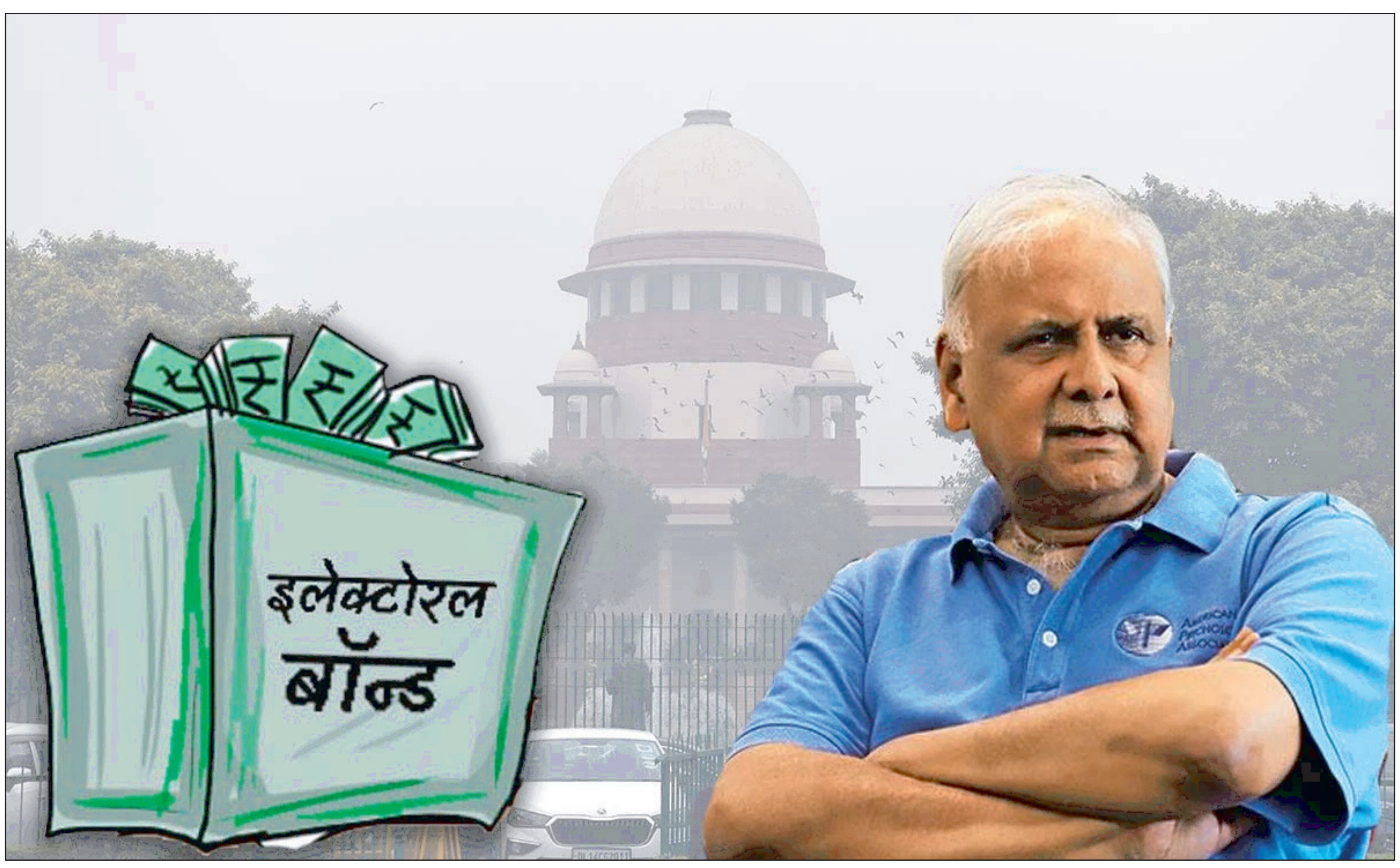

चुनाव के ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 'चुनावी बॉन्ड योजना' को असंवैधानिक करार देकर सियासी दलों में कोहराम मचा दिया है। सत्ताधारी दल के लिए ये चोर दरवाजे से प्राप्त करने वाली ऐसी व्यवस्था थी जिस पर कोई उंगली भी नहीं उठाता था और कुल मिलाकर उनका ही एकछत्र राज भी था। इस योजना से विपक्षी दलों के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। चंदेदारों द्वारा विगत 5 वर्षों में जितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, वो सभी सत्ताधारी के ही नाम रहे। किसने कितना धन दिया? देने वाला कौन है, कहां का है, क्या करता है? किसी को कुछ नहीं पता? सूचना के अधिकार से भी दूर रखा। पर, अब इस व्यवस्था पर कोर्ट ने ऐसा चाबुक चलाया है जिससे सियासी दलों से कुछ बोलते नहीं बनता। ये अलख जगाई है प्रो. जगदीप एस. छोकर ने जो विश्व प्रसिद्ध 'एडीआर' संस्थान के संस्थापक हैं। उनसे विस्तृत बातचीत हुई पत्रकार डॉ. रमेश ठाकुर द्वारा। पढ़ें बातचीत के कुछ चुनिंदा अंश इस साक्षात्कार में।

प्रश्न- सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार चुनावी बांड को असंवैधानिक बता दिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?

उत्तर- पेचिदगियां हैं अभी कई सारी। फैसले को मैं 'देर आए दुरुस्त आए' ही कहूंगा। क्योंकि निर्णय कुछ महीनों से कोर्ट में रिजर्व था। जिसे काफी पहले सुनाया जाना चाहिए था। निर्णय को दो भागों में लिखा गया। पहले निर्णय को चार जजों ने और दूसरे निर्णय को एक अन्य जज ने लिखा। बहरहाल दोनों की भाषा एक ही है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में हैं। कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह का वक्त दिया है जिसमें उन्हें संपूर्ण चंदे के राशि और दानदाताओं की पूरी सूचना सार्वजनिक करनी है। करीब एक सप्ताह तो बीत चुका है। मोटा-मोटा आंकड़ा तो 16000 करोड़ रुपए का है। देखते हैं, चुनाव आयोग कितना पैसा दर्शाता है और सभी के नाम उजागर करता है या नहीं?

प्रश्नः इलेक्टोरल बॉन्ड में कमियां क्या थीं?

उत्तर- खामियां कोई एक थोड़ी थी, बहुतेरी थीं। अव्वल, तो यही कि न तो धन के स्त्रोत का पता चल पाता था और न ही देने वाले का परिचय? लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे पीछे हाथ से रिश्वत लेना कहते हैं। एक दिक्कत और थी इसमें सबसे बड़ी। रूलिंग पार्टी के हिस्से ही आता था सारा का सारा इलेक्टोरल बांड। बाकी विरोधी पार्टियां तो ठनठन गोपाल रहती थीं। 2017 से अगर देखें तो तकरीबन एक तिहाई यानी 75 फीसदी चुनावी बांड की रकम सत्ताधारी दल के खाते में गई। बाकी अन्य दलों को मात्र 25 फीसदी से संतोष करना पड़ा। ये बात सार्वजनिक हो चुकी थी कि ये व्यवस्था खुलेआम रूलिंग दल को फायदा पहुंचाती थी। पैसे और उसके स्वामी के संबंध में जानकारी पब्लिक डोमेन में रत्ती भर पहुंचने नहीं दी जाती थी।

प्रश्नः अगर ये व्यवस्था बंद हुई, तो आपको नहीं लगता, चुनावी चंदे का गड़बडझाला फिर से पुराने समय जैसा लौट जाएगा?

उत्तर- निश्चित रूप से इस तरह के अंदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता। सियासी दल बिना चंदे के चल ही नहीं सकते। चुनावों में उन्हें पैसा चाहिए ही होगा। फिर चाहे वो पैसा उन्हें काले धन के रूप में मिले, या फिर कोई छंटा हुआ अपराधी ही क्यों न दे। हम सभी देखते हैं कि चुनाव आज कितने खर्चीले हो गए हैं। गांव के प्रधानी चुनाव में भी कई लाख रुपए लोग खर्च कर देते हैं। लोकसभा-विधानसभा चुनाव में पार्टियां पानी की तरह पैसा बहाती हैं। प्रत्येक चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से करोड़ों-अरबों रुपए पकड़े जाते हैं। वो पैसा सीधे-सीधे काला धन ही होता है। ये भविष्य में भी होगा। अगर नहीं होगा तो उसका कोई अलहदा तरीका सियासी दल खोजेंगे। तब, हमारी लड़ाई उन तरीकों का भी पीछा करेगी। बिना चंदे के गुजारा कहां, खोजेंगे नया कोई न कोई तरीका।

प्रश्नः चुनावी चंदे का धंधा बंद हो, इसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए?

उत्तर- बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान भी? चुनावों में उम्मीदवारों के लिए धन खर्च करने का निर्धारण तय होना चाहिए। सीमित धन में अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, तो व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। पर, एक सच्चाई ये भी है कि अभी तक धन खर्च करने की जितनी छूट है, उतना तो एक उम्मीदवार रैली में भाड़े के हेलीकाप्टर पर खर्च कर देता है। क्या ये सब चुनाव आयोग को नहीं दिखता। देखिए, किसी भी व्यवस्था या नियम का मकसद यही होता है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन, बल का हस्तक्षेप न हो और स्वच्छ चुनाव हों। इसके लिए कठोर कानून की जरूरत है और चुनाव आयोग को प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। कागजी और दिखावटी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के विक्रय करने वाले 'स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया' को 3 हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करने का जो निर्देश दिया, उसमें कई सारी बातें साफ हो जाएंगी।

प्रश्नः चुनावी बांड को सूचना के अधिकार से भी अलग रखा गया?

उत्तर- मैंने कहा न, ये व्यवस्था खुलेआम डाका डालने जैसी है। कई कानूनों में संशोधन करके इस व्यवस्था को जन्मा गया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक माना। ये सीधे-सीधे सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पिछले 5 वर्षों मिले चंदे का हिसाब-किताब भी देने को कहा है। देखना, यहां भी आनाकानी होगी। विपक्षी दल भी ब्यौरा देने से कतराएंगे। कहने को तो चुनावी बॉन्ड एक वचन-पत्र या धारक बांड की प्रकृति का उपकरण है, जिसे किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति या निकाय भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित हो। लेकिन इसमें खामियां और पर्दादारी कितनी रखी गई, उसे सार्वजनिक करने से सभी की सांसें फूलती रहीं।

प्रश्नः चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करने में आखिर परहेज क्या है?

उत्तर- क्यों परहेज नहीं है? कोई किसी को खैरात में धन क्यों देगा? सामने वाले से फायदा उठाने के मकसद से ही अपना धन लुटाएगा। देने और लेने वाले के मध्य एक बकायदा गुप्त एग्रीमेंट होता है। कोई धन्नासेठ जब किसी दल को बड़ी रकम देता है, तो बाद में टेंडर या कोई बड़ा काम निकलवाता है। कुछ तो कानून में भी बदलाव करवाते हैं। सियासी दलों को गुमनामी चंदा ज्यादातर बड़े उद्योगपतियों व औद्योगिक घरानों से मिलता है। चंदा देने के बाद ये अपना हित साधते हैं। चंदा खाने के बाद सरकारों को भी तमाम नीतियां उन्हीं के मनमाफिक बनानी पड़ती हैं। तभी तो वो जमकर पानी का दोहन करती हैं, जंगलों की कटाई करने से भी बाज नहीं आती। उनके कृत्य को देखकर जनता चीखती-चिल्लाती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता उसमें दोनों की मिलीभगत होती है।

बातचीत में जैसा प्रो. जगदीप एस. छोकर ने कहा।

इनसाइड

भारत के बॉन्ड मार्केट पर बड़ा दांव लगा रहे FPI, जानिए फरवरी में कितना किया निवेश?

FPI ने फरवरी में भारत के बान्ड मार्केट में साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। वहीं जनवरी में FPI ने बॉन्ड बाजार में 19836 करोड़ रुपये से अधिक लगाया था जो पिछले 6 साल के दौरान किसी एक महीने में FPI की ओर से सबसे ज्यादा निवेश है। ओवरऑल रिकॉर्ड जून 2017 में बना था जब FPI ने देश के बॉन्ड मार्केट में 25685 करोड़ रुपये डाले थे।

नई दिल्ली। फॉरेन पोर्टफोलियो इनवेस्टर्स (Foreign Portfolio Investors or FPI) का भारत के कर्ज या बॉन्ड मार्केट में दिलचस्पी बनी हुई है। इसकी एक अहम वजह भारत सरकार के बॉन्ड को सबसे बड़े अमेरिकी बैंक जेपी मॉर्गन के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने का फैसला है।

अगर इस महीने या फरवरी की बात करें, तो FPI ने भारत के बॉन्ड मार्केट में साढ़े 18 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। वहीं, जनवरी में FPI ने बॉन्ड बाजार में 19,836 करोड़ रुपये से अधिक लगाया था, जो पिछले 6 साल के दौरान किसी एक महीने में FPI की ओर से सबसे ज्यादा निवेश है।

सबसे अधिक निवेश का ओवरऑल रिकॉर्ड जून 2017 में बना था, जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने देश के बॉन्ड मार्केट में 25,685 करोड़ रुपये डाले थे।

अगर 2024 के शुरुआती दो महीनों यानी जनवरी और फरवरी को मिलाकर देखें, तो बॉन्ड मार्केट में FPI का कुल इनवेस्टमेंट 38,426 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है। पिछले साल के आखिरी तीन महीनों की बात करें, तो FPI ने दिसंबर में 18,302 करोड़ रुपये, नवंबर में 14,860 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 6,381 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट किया था।

जेपी मॉर्गन ने पिछले साल सितंबर में ऐलान किया था कि वह जून 2024 से भारत सरकार के बॉन्ड को अपने बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम था, जो अगले डेढ़ से दो साल के दौरान भारत में 20 से 40 अरब डॉलर का निवेश लाने में मदद करेगा।

अगर निकासी के आंकड़ों पर गौर करें, तो इस महीने अब FPI ने शेयर मार्केट से करीब 424 करोड़ रुपये निकाले हैं। हालांकि, यह जनवरी के मुकाबले काफी कम है, जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 25,743 करोड़ रुपये की भारी निकासी की थी।

FPI का मानना था कि भारत के शेयर मार्केट की वैल्यूएशन ऊंची है। साथ ही अमेरिका में बॉन्ड पर बढ़ती यील्ड में भी उन्हें ज्यादा लाभ दिखा। FPI ने सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग स्टॉक्स में की है। गोल्डमैन सैक्स ने निकट भविष्य में बैंकिंग सेक्टर के खराब प्रदर्शन का अनुमान जताते हुए कई बैंकों की रेटिंग घटाई थी।

आठ सालों में 1877 नए उत्पादों का शुरू किया गया निर्यात, ऑस्ट्रेलिया-सिंगापुर में तेजी से बढ़ रहा है भारतीय निर्यात

परिवहन विशेष न्यूज

वस्तु निर्यात के वैश्विक बाजार में पिछले आठ सालों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात शुरू किया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चीन से होने वाले आयात में चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जनवरी में पिछले वित्त वर्ष समान अवधि की तुलना में सिर्फ 2.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि रूस से होने वाले आयात में इस अवधि में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई ।

नई दिल्ली। वस्तु निर्यात के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और पिछले आठ सालों में 1877 नए उत्पादों का निर्यात शुरू किया गया है। वस्तुओं के साथ निर्यातकों की संख्या भी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और फिर से यह संख्या कोरोना पूर्व काल पर पहुंच गई है। नए-नए बाजार की भी तलाश जारी है।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल-जनवरी में आस्ट्रेलिया और सिंगापुर होने वाले निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमशः 16.19 व 12.81 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि इस अवधि में अमेरिका व जर्मनी होने वाले निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले क्रमशः 4.01 व 5.35 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि अमेरिका अब भी भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना हुआ है।

44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, चीन से होने वाले आयात में चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जनवरी में पिछले वित्त वर्ष समान अवधि की तुलना में सिर्फ 2.58 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है जबकि रूस से होने वाले आयात में इस अवधि में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्विटजरलैंड से होने वाले आयात में 34 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

8 सालों में 1877 नए आइटम का निर्यात शुरू करने में सफलता

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 से लेकर गत वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि में 2105 नई वस्तुएं निर्यात बास्केट में जोड़ी गई, हालांकि इनमें से 228 उत्पाद ऐसे थे जिनका पिछले आठ सालों में कोई निर्यात नहीं किया जा सका।

इस लिहाज से पिछले आठ सालों में 1877 नए आइटम का निर्यात शुरू करने में सफलता मिली है। मंत्रालय के मुताबिक कोरोना काल में निर्यातकों की संख्या घटकर 1.51 लाख हो गई थी जो अब कोरोना पूर्व काल के आंकड़ों को पार करते हुए 1.63 लाख पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2017-18 में देश में 1.62 लाख निर्यातक थे।

निवेश से पैसा बढ़ाने के साथ बचेगा टैक्स, आपके लिए ही हैं ये 5 स्कीम

नया वित्त वर्ष शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आपको अभी से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए निवेश योजना तैयार कर लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न तो मिले ही साथ में टैक्स की भी बचत हो। हम पांच स्कीमों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शानदार रिटर्न देंगी और टैक्स में छूट भी दिलाएंगी।

नई दिल्ली। नया वित्त वर्ष शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आपको अभी से अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए निवेश योजना तैयार कर लेनी चाहिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न तो मिले ही, साथ में टैक्स की भी बचत हो। हम पांच स्कीमों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको शानदार रिटर्न देंगी और टैक्स में छूट भी दिलाएंगी। लेकिन, आपको ध्यान रखना होगा कि ये फायदे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उठा सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

टैक्स बचाने और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट के लिए लिहाज नेशनल पेंशन सिस्टम एक अच्छा विकल्प है। इसमें इनकम टैक्स कानून की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50 हजार रुपये की टैक्स छूट मिल सकती है। इसमें हर साल के इनवेस्टमेंट पर टैक्स छूट का लाभ तो मिलता है, साथ ही आगे चलकर पेंशन आपके बुढ़ापे की लाठी भी बनता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी लॉन्ग टर्म स्कीम है। यह 15 साल में मेच्योर होती है, जिसे 5-5 साल के ब्लॉक्स में आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 500 से लेकर 1.5 लाख रुपये निवेश किए जा सकते हैं। इस पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। यह निवेश धारा 80सी के तहत आपको सालाना डेढ़ लाख रुपये की छूट दिला सकता है।

रेरा पर नहीं लगेगा जीएसटी, जल्द स्पष्टीकरण जारी कर सकती है काउंसिल

परिवहन विशेष न्यूज

जीएसटी काउंसिल जल्द ही यह स्पष्ट कर सकती है कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र का नियामक रेरा संविधान के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत आता है जो पंचायतों की शक्तियों अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इस संबंध में रेरा अधिकारियों से भी चर्चा की गई।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल जल्द ही यह स्पष्ट कर सकती है कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) को जीएसटी का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक अधिकारी ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र का नियामक रेरा संविधान के अनुच्छेद 243जी के अंतर्गत आता है, जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और विवादों शीघ्र निपटान के लिए एक निर्णय तंत्र के रूप में विभिन्न राज्यों में रेरा की स्थापना की गई है। अधिकारी ने कहा कि रेरा के अधिकारियों के साथ उनके कामकाज की प्रकृति के बारे में चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि उन पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

अधिकारी ने आगे कहा कि रेरा को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और इसलिए जीएसटी लगाने का मतलब राज्य सरकारों पर कर लगाना होगा। अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता और राज्यों के मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की बैठक हो सकती है।

जीएसटी परिषद की पिछली बैठक सात अक्टूबर 2023 को हुई थी। Moore Singhi के कार्यकारी निदेशक रजत मोहन ने कहा कि 18 जुलाई, 2022 से पहले आरबीआइ, सेबी, इरडा, एफएसएसएआइ सहित प्रमुख नियामक निकायों द्वारा दी जाने वाली कुछ सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं थी। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई, 2022 को यह छूट हटा ली गई, जिसके बाद यह बात सामने आई कि क्या रेरा को जीएसटी को भुगतान करना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा आवासीय रियल एस्टेट सेक्टर में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) की अनुमति नहीं है, जिसका मतलब यह हुआ कि अगर रेरा को जीएसटी से बाहर रखा जाता है तो डेवलपर्स और घर खरीदारों दोनों को राहत मिलेगी।

स्टॉक एक्सचेंजस ने IOC, GAIL और ONGC पर लगातार तीसरी तिमाही में लगाया जुर्माना, जानें इसकी वजह

स्टॉक एक्सचेंज ने ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी कई सरकारी कंपनियों पर जरूरी नियमों का पालन करने की वजह से लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया है। सरकार के मालिकाना हक वाली इंडियन ऑयल ONGC और GAIL जैसी कंपनियां अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करने में नाकाम रहीं। कंपनियों की दलील है कि ये नियुक्तियां सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं

नई दिल्ली। स्टॉक एक्सचेंज ने ऑयल और गैस सेक्टर से जुड़ी कई सरकारी कंपनियों पर जरूरी नियमों का पालन करने की वजह से लगातार तीसरी तिमाही में जुर्माना लगाया है। सरकार के मालिकाना हक वाली इंडियन ऑयल, ONGC और GAIL जैसी कंपनियां अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करने में नाकाम रहीं।

इन कंपनियों ने अलग-अलग फाइलिंग में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही में स्वतंत्र निदेशकों या अनिवार्य महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं होने के कारण बीएसई और एनएसई के लगाए गए जुर्माने की जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ये नियुक्तियां सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और इनमें उनका कोई रोल नहीं है। पिछली दो तिमाहियों में भी इन कंपनियों पर इसी वजह से जुर्माना लगाया गया था।

छह सार्वजनिक उपक्रमों ने अलग-अलग फाइलिंग में बताया कि शेयर बाजार ने उन पर तीसरी तिमाही के लिए 5,42,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। ONGC और उसकी सहायक कंपनियों HPCL और MRPL के साथ GAIL और OIL के बोर्ड में जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। वहीं, IOC के बोर्ड एक भी महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं होने की वजह से जुर्माने का सामना करना पड़ा।

लिस्टिंग मानदंडों के अनुसार, कंपनियों को कार्यकारी निदेशकों के समान अनुपात में स्वतंत्र निदेशक भी रखना होता है। साथ ही, बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक हर हाल में होनी चाहिए। दूसरी तिमाही में IOC, ONGC, OIL, GAIL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को इसी वजह से जुर्माना झेलना पड़ा था।

IOC ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, 'एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास है। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने की वजह कंपनी की कोई लापरवाही या गलती नहीं है।' IOC ने कहा कि इसलिए उसका जुर्माना माफ कर दिया जाना चाहिए।

इस हफ्ते आने वाले हैं 6 आईपीओ, निवेश से पहले जान लीजिए उनकी पूरी डिटेल्स

इस वक्त शेयर बाजार को निवेश के लिहाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई स्टॉक्स और IPO (Initial Public Offering) ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। हम अगले हफ्ते आने वाले छह IPO के बारे में बता रहे हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हैं। इन आईपीओ से कंपनियां 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने वाली हैं।

नई दिल्ली। इस वक्त शेयर बाजार को निवेश के लिहाज लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में कई स्टॉक्स और IPO (Initial Public Offering) ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। हम अगले हफ्ते आने वाले छह IPO के बारे में बता रहे हैं, जिन पर आप दांव लगा सकते हैं। इन आईपीओ से कंपनियां 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाने वाली हैं।

भारत हाईवेज इनविट (Bharat Highways Invit)

इस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का 2,500 करोड़ रुपये का आईपीओ 28 फरवरी को खुलेगा और 1 मार्च को बंद होगा। मूल्य दायरा 98-100 रुपये प्रति यूनिट है। निवेशक एक लॉट में न्यूनतम 150 यूनिट और उसके आगे 150 यूनिट के गुणक में बोली लगा सकते हैं।

प्लैटिनम इंडस्ट्रीज (Platinum Industries)

मेनबोर्ड से लेकर स्टेबलाइजर बनाने वाली प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का 27 फरवरी खुलेगा। निवेशक इसे 29 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकेंगे। प्राइस बैंड 162-171 रुपये प्रति शेयर रहेगा। कंपनी का आईपीओ से 235.32 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान है।

एक्सिकॉम टेली-सिस्टम्स (Exicom Tele-Systems)

ईवी चार्जिंग सेगमेंट की पहली कंपनी एक्सिकॉम ने 27-29 फरवरी के बीच 429 करोड़ रुपये का IPO लाएगी। इसका प्राइस बैंड 135-142 रुपये प्रति शेयर रहेगा। इस आईपीओ से 429 करोड़ रुपये जुटाने का टारगेट है। 329 करोड़ रुपये फ्रेश इश्यू के जरिए, जबकि 100 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल (OFS) के लिए रिजर्व हैं।

ओवैस मेटल एंड मिनरल प्रोसेसिंग आईपीओ

यह SME सेक्टर की कंपनी है। मेटल और मिनरल का उत्पादन और प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी का आईपीओ 26 फरवरी को खुलेगा और 28 फरवरी तक सब्सक्राइब किया जा सकेगा। इसका प्राइस बैंड 83-87 रुपये प्रति शेयर है।

पूर्व फ्लेक्सीपैक आईपीओ (Purv Flexipack IPO)

फ्लेक्सिबल पैकेजिंग से जुड़ा कारोबार करने वाली पूर्व फ्लेक्सीपैक का आईपीओ 27 फरवरी को खुलेगा और 29 को बंद होगा। प्राइस बैंड 70 से 71 रुपये प्रति शेयर है। 40.21 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयरों का है।

एमवीके एग्रो फूड प्रोडक्ट आईपीओ

शुगर और उससे जुड़े दूसरे प्रोडक्ट बनाने वाली इस कंपनी का 65.88 करोड़ रुपये का आईपीओ 29 फरवरी से 4 मार्च के बीच सदस्यता के लिए खुलेगा। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 120 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।

एक दशक में डबल हुआ परिवारों का खर्च, हेल्थ-एजुकेशन पर बढ़ा फोकस

पिछले करीब एक दशक में देश के परिवारों का हर महीने का खर्च दोगुना से भी अधिक बढ़ गया है। इस दौरान परिवार के हर शख्स के घरेलू खर्च में भी बड़ा इजाफा दिखा है। यह जानकारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ सि (NSSO) की स्टडी से मिली है जिसने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक देशभर में घरेलू खर्च को लेकर सर्वे क यिा था।

नई दिल्ली। पिछले करीब एक दशक में देश के परिवारों का हर महीने का खर्च दोगुना से भी अधिक बढ़ गया है। इस दौरान परिवार के हर शख्स के घरेलू खर्च में भी बड़ा इजाफा दिखा है। यह जानकारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की स्टडी से मिली है, जिसने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 तक देशभर में घरेलू खर्च को लेकर सर्वे कयिा था।

NSSO ने अपने सर्वे में पाया कि 2022-23 में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों का हर महीने का औसतन खर्च 3,773 रुपये पर पहुंच गया है, जो 2011-12 में 1,430 रुपये था। वहीं, शहरी परिवारों की बात करें, तो उनका खर्च इस दौरान 2,630 रुपये से बढ़कर 6,459 रुपये हो गया।

NSSO के सर्वे के अनुसार Monthly Per-capita Consumer Expenditure (MPCE) शहरी क्षेत्रों में 2011-12 में 2,630 रुपये से बढ़कर 3,510 रुपये हो गया। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,430 रुपये से बढ़कर 2,008 रुपये हो गया। शहरी क्षेत्रों में मौजूदा कीमत पर औसत MPCE 2011-12 के 2,630 रुपये से बढ़कर 2022-23 में 6,521 रुपये तक पहुंच गया।

ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो यह 1,430 रुपये से बढ़कर 2,054 रुपये हो गया है। MPCE का अनुमान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले केंद्रीय नमूने में 2,61,746 घरों से जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 1,55,014 और शहरी क्षेत्र के 1,06,732 घर शामिल हैं।

क्यों किया जाता है यह सर्वे?

Ministry of Statistics and Programme Implementation के अंतर्गत आने वाला NSSO यह सर्वे साल करता है। इसका मकसद यह पता लगाना होता है कि आम आदमी के खर्च में किस तरह से बदलाव हो रहा है। अलग-अलग राज्यों और शहरों में लोगों के खर्च करने का पैटर्न क्या है।

सर्वे से एजुकेशन और हेल्थ जैसी बुनियादी चीजों के बारे में भी पता चलता है, जिन पर लोग पहले की तुलना में अब ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सरकार को इस सर्वे के आधार पर अपनी योजनाएं बनाने में भी मदद मिलती है।

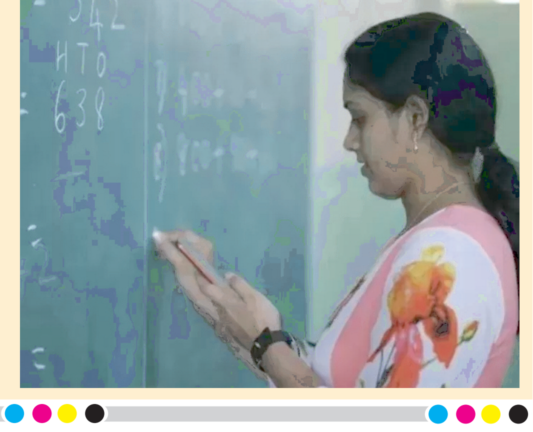

देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन

लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से बना यह केबल ब्रिज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है. सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल है.

परिवहन विशेष न्यूज

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं. वह आज सुबह बेट द्वारका मंदिर पहुंचे और यहां दर्शन-पूजन किया. इसके बाद उन्होंने नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद रहे. लगभग 980 करोड़ रुपये की लागत से बना यह केबल ब्रिज ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है. सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल है. इसकी लंबाई 2.32 किलोमीटर है.

प्रधानमंत्री द्वारकाधीश मंदिर भी जाएंगे और वहां दर्शन-पूजा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 52,250 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, सड़क, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हैं. पीएम आज राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी एम्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पीएम नरेन्द्र मोदी नई मुंद्रा-पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे. वह राजकोट-ओखा, राजकोट-जेतलसर-सोमनाथ और जेतलसर-वांसजालिया रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम गुजरात पहुंचे. जामनगर में उन्होंने देर रात रोड शो किया. इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उनके स्वागत के लिए उमड़ा. सड़कों के दोनों ओर लोग कतारों में खड़े थे और पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश की. इसके अलावा प्रधानमत्री मोदी 23 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 11,500 करोड़ रुपये से अधिक की 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे.

तीतरों क्षेत्र में पुलिस के जबरदस्त सघन वाहन चेकिंग अभियान के चलते हेलमेट खरीदने वालों की दुकानों पर लगी होड़

- थाना तीतरो प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में भिन्न भिन्न स्थानों पर जारी है,वाहन चेकिंग अभियान
- तीतरों क्षेत्र के ग्रामीण बोले अब हमारे बच्चों की सुरक्षा हेलमेट ही करेगा,सभी ने जताया पुलिस का आभार

परिवहन विशेष न्यूज

सहारनपुर। दोपहिया वाहन चलाते समय सिर पर हेलमेट लगाना अनिवार्य है,यह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आवश्यक तथा आपकी जान बचाने के लिए भी जरूरी है, इसलिए हेलमेट को अपने सिर पर बोझ ना समझे और वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का उपयोग करें,क्योंकि दोपहिया वाहन चलाते समय होने वाली सड़क दुर्घटनाओ में ज्यादातर मौतें सिर में लगी गम्भीर चोटो के कारण ही होती है। हेलमेट दुर्घटनाओ के समय सिर में चोंट लगने से बचाता है।इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग जरूरी है।जबकि यातायात अधिकारी भी कहते हैं,कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ, यातायात नियमों का पालन करोगे,तो बची रहेगी आपकी जान।इसलिए हेलमेट लगाकर ही दुपहिया वाहन चलाए।जी हां हम बात कर रहे हैं वाहन चेकिंग अभियान की,जो तीतरो क्षेत्र में लगातार जारी है।इस लगातार वाहन चेकिंग अभियान के चलते हेलमेट खरीदने वालों की दुकानों पर होड लगी है,जिसे देखो वही हेलमेट खरीदता हुआ नजर आया।जब इन लोगों से हेलमेट खरीदने का रिजन पुछा गया,तो उनका एक ही कहना था,कि भाई पुलिस बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों के चालान कर रही है,हम आपको बता दें,कि सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट का उपयोग नहीं होता है,बल्की यह आपकी जान भी बचाता है हेलमेट।तीतरों क्षेत्र में दोपहिया व चार पहिया वाहन चेकिंग के चलते वाहन चलाने वालों मे भारी खलबली मची हुई,हर कोई दुकानों या फिर सड़क किनारे बैठकर हेलमेट की दुकान चलाने वालों से हेलमेट खरीदते नजर आया।इधर तीतरों क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों तक का कहना है,कि उनके बच्चों की सुरक्षा हेलमेट कर रहा है,उन्होंने इस वाहन चेकिंग अभियान की दबाकर सराहना की।इधर थाना तीतरों इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिंह का कहना है,कि दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाए,क्योंकि आपका घर कोई इंतजार कर रहा है।उन्होंने कहा,कि हेलमेट चालान ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भी बचाता है।उन्होंने कहा कि हेलमेट चेकिंग के पीछे पुलिस की मंशा बाईक चालकों की सुरक्षा होती है, इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट लगाए।

अर्चना चिटनिस की पहल, जीरो वेस्ट इवेंट बना सामूहिक विवाह समारोह

मुख्यमंत्री कन्यादान-निकाह योजना के तहत 403 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ।

परिवहन विशेष न्यूज

बुरहानपुर। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा से पहली बार सामूहिक विवाह समारोह एक विजन बन गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में पहली बार प्लॉस्टिक का उपयोग नहीं हुआ तो विधायक एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनिस (दीदी) की पहल पर सामूहिक विवाह समारोह ''जीरो वेस्ट इवेंट'' बन गया। जिससे कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता और साफ-सफाई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यहां आएं वर-वधु एवं उनके परिजनों ने श्रीमती चिटनिस के प्रयासों और नवाचार को मूर्तरूप दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान-निकाह योजना के तहत 403 जोड़ों का विवाह और निकाह संपन्न हुआ। इसमें रेणुका कृषि उपज मंडी प्रांगण में 119 वर-वधु परिणय सूत्र में बंधे। इसी प्रकार खंडवा मार्ग स्थित कृषि उपज मंडी में आयोजित निकाह समारोह में 284 जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया। रेणुका कृषि उपज मंडी का आयोजन शत-प्रतिशत जीरो वेस्ट एवं न्यूनतम प्लॉस्टिक का उपयोग के साथ संपन्न हुआ।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि हमनें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन में सहभागिता निभाने की दृष्टि से जीरो वेस्ट आयोजन के संकल्प लिया था जो काफी हद तक सफल रहा। उन्होंने कहा कि पंजीयन के समय ही आवेदकों से अनुरोध किया गया था कि वे भी अपनी जिम्मेदारी स्वरूप जीरो प्लॉस्टिक की वस्तुओं का उपयोग करें। मिनिमम या जीरो प्लास्टिक वेस्ट को प्रतिबद्धता के साथ लागू कर सामारोह आयोजित हुआ। इस हेतु सभी वर-वधु और परिजनों का मन से आभार व्यक्त करती हूं। श्रीमती चिटनिस ने कहा कि हम सभी सामूहिकता के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के स्वच्छ भारत के विजन को साकार कर सकते है यह हमें विश्वास है।

श्रीमती चिटनिस ने कहा कि शहर को पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए आयोजित विवाह समारोह में जीरो वेस्ट फॉर्मूले को अपनाते हुए उसे सफल बनाने का प्रयास कर नवाचार किया गया। समारोह में न्यूनतम प्लास्टिक का उपयोग ही किया गया। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से एक सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा कि अगर 419 विवाह जीरो वेस्ट और बिना प्लॉस्टिक के उपयोग के साथ संपन्न हो सकता है तो हम अपने व्यक्तिगत समारोह और आयोजनों को भी जीरो वेस्ट और बिना प्लॉस्टिक का उपयोग कर आसानी से कर सकते है। हमें इसके लिए नगरीय निकायों और पंचायतों के माध्यम से जन जागरण करना होगा। व्यक्तिगत समारोह और सामुदायिक समारोह में भी जीरो वेस्ट को जन जागरण कर एक उदाहरण बन सकेंगा।

श्रीमती अर्चना चिटनिस ने कहा कि इसके साथ ही आगामी दिवसों में नव दंपती को धनादेश के साथ ही उपहार स्वरूप कपड़े की थैली भेंट की जाएगी ताकि जीवन पर्यन्त प्लास्टिक की थैली का उपयोग न करने की प्रेरणा होगी।

पारिवारिक उपभोग के खर्च में कम होने लगी गांव और शहरों की दूरी, सरकारी प्रयास का दिखने लगा असर

नई दिल्ली। देश के समग्र विकास को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयास का असर दिखने लगा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय व राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाके में पारिवारिक उपभोग पर होने वाले खर्च में अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ कि पारिवारिक उपभोग पर होने वाले मासिक खर्च में शहरों और गांवों के बीच के अंतर में कमी आने लगी है। ग्रामीण इलाके में खाने पर होने वाले खर्च में भी पहले के मुकाबले कमी आई है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2011-12 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में पारिवारिक उपभोग के मासिक खर्च में ग्रामीण इलाके में 164 प्रतिशत तो शहरी इलाके में 146 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। 2011-12 में ग्रामीण इलाके में पारिवारिक उपभोग पर एक परिवार का मासिक खर्च 1430 रुपए था जो 2022-23 में बढ़कर 3773 रुपए हो गया। शहर में यह खर्च वर्ष 2011-12 में 2630 रुपए था जो 2022-23 में 6459 रुपए हो गया।

भोट फिल्म मे MLA की अभिनय मे नयी तारका रंजन राउत

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : *भुबनेश्वर रसुलगढ़ सिनेपोलिश मे भोट फिल्म रिलीज़ हुई ।रुतुप्रिया प्रोडक्शन हाउस का वोट फिल्म । अतिश राउत प्रजोजित अजय महापात्र निर्देशित फिल्म मे उशासी मिश्र , रानू पाढ़ी , हर रथ जैसे सीनियर कलाकार अभिनय किये ।रंजन राउत पहेली बार इसी भोट फिल्म मे अभिनय किया हैं , उनकी अभिनय को दर्सक ने तारीफ की । एक बार फिल्म देखने केलिए प्रजोजक अतिश राउत ने दर्सक को अपील की ।*

कांग्रेस की चेतावनी: BJD के लिए काम करने वाले सरकारी अधिकारियों की सूची जल्द जारी की जाएगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर् : राज्य का प्रशासन अब मुट्ठी भर सरकारी अधिकारियों के हाथ में है। ये सरकारी अधिकारी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रचार के तहत खुलमखुला बीजेडी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही इन अधिकारियों की पहचान कर ली है और आज चेतावनी दी है कि वह जल्द ही उनकी सूची जारी करेगी ।पीसीसी अभियान समिति के अध्यक्ष विजय पटनायक ने आज कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नवीन पटनायक की सरकार ने ओडिशा की शासन व्यवस्था को सरकारी अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया है । कांग्रेस इन अफसरों पर नजर रख रही है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है । इन दिनों आईएएस, ओएएस अधिकारी सरकारी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों ने विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की जिम्मेदारी ले ली है । वे सरकारी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है । आज यहां बैठे लाखों अभ्यर्थियों में से जो अपनी मेहनत से सफल हुए हैं। श्री पटनायक ने कहा कि अगर वे उनके कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो जायेगी ।उन्होंने हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनियमितताएं करने वाले सरकारी अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त कर दिया था और इंडिया मेंटर के पराजित उम्मीदवार की जीत हुई थी। बिल्कुल वैसा ही उदाहरण ओडिशा में कार्यरत कुछ सरकारी अधिकारियों को देखना चाहिए। श्री पटनायक ने चेतावनी दी कि इसका जवाब उन्हें संबोधन के दौरान दिया जायेगा ।

इन अधिकारियों को लोक सेवकों के लिए बने नियमों को पढ़ना चाहिए और सावधान रहना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य करना है। श्री पटनायक ने कहा, ₹अगर वे बीजू जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करना जारी रखेंगे, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सड़कों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और चुनाव आयोग को रिपोर्ट करेगी।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसीसी प्रवक्ता हामिद हुसैन, निशिकांत मिश्रा और अभिषेक महानंद मुख्य रूप से शामिल हुए ।

भारत 2032 तक 18 और परमाणु क्षमता वाले बनाएगा रिएक्टर, फिलहाल 24 हो रहे संचालित

भारत 13800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले 18 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाएगा जिससे 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी 22480 मेगावाट हो जाएगी। नपीसीआइएल ने कहा कि केएपीएस तीन और चार उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले सबसे बड़े स्वदेशी दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हैं जो दुनिया के मानकों के बराबर हैं। इन रिएक्टरों को एनपीसीआइएल द्वारा डिजाइन निर्मित चालू और संचालित किया गया है।

नई दिल्ली। भारत 13,800 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता वाले 18 और परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बनाएगा, जिससे 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा की कुल हिस्सेदारी 22,480 मेगावाट हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले सप्ताह गुजरात के काकरापार में दो घरेलू निर्मित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को देश को समर्पित करने के बाद न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) ने इसकी घोषणा की थी। वर्तमान में एनपीसीआइएल 8,180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालित करता है।

पीएम मोदी ने 22 फरवरी को किया था राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी को काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट तीन और चार को राष्ट्र को समर्पित किया था। उनकी काकरापार यात्रा से दो दिन पहले 20 फरवरी को केएपीएस-4 को पश्चिमी पावर ग्रिड से जोड़ा गया था। एनपीसीआइएल ने कहा कि केएपीएस तीन और चार उन्नत सुरक्षा सुविधाओं वाले सबसे बड़े स्वदेशी दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) हैं, जो दुनिया के मानकों के बराबर हैं।

एनपीसीआइएल करता है संचालित

इन रिएक्टरों को एनपीसीआइएल द्वारा डिजाइन, निर्मित, चालू और संचालित किया गया है। इसमें उपकरणों की आपूर्ति और भारतीय कंपनियों द्वारा अनुबंधों का निष्पादन किया गया है। यह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। रूसी सहायता से तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1,000 मेगावाट के चार परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाए जा रहे हैं।

अपील - विद्यार्थियों पर अधिक नंबर या परसेंटेज लाने के लिए दबाव ना बनाएं : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान

माता-पिता व अभिभावक अपने बच्चे को भरोसा दिलाएं कि वे परीक्षा में बेहतर करेंगे : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान

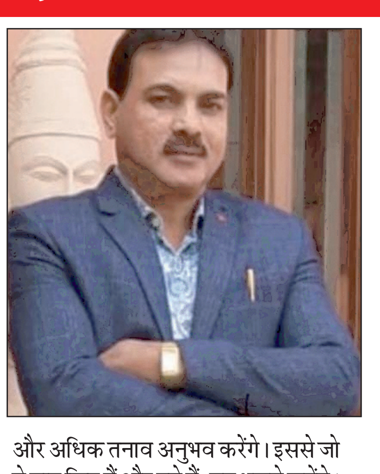

आगरा। बोर्ड की परीक्षाओं में सभी अभिभावकों की अपेक्षा रहती है कि उनकी संतान परीक्षा अच्छे से अच्छा नंबर लाए। इसी अपेक्षा में वे जाने-अनजाने बच्चों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव और तनाव डाल देते हैं। जिसके चलते उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती और विद्यार्थियों के मन में निराशा की भावना आ जाती है। कई बार परीक्षा में असफल होने या अभिभावकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरने पर विद्यार्थी गलत कदम भी उठा लेते हैं।

सन्दर्भ में लोकप्रिय व सुप्रशिद्ध वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ खान ने बताया कि यह परीक्षाओं का समय है। पढ़ाई के लिए दबाव बनाना वास्तव में बच्चों पर और अधिक तनाव डालना है। अभिभावक अपने बच्चों को यह जरूर कहें कि हम जानते हैं कि तुम परीक्षा में अच्छी परफारमेंस के लिए तैयार हो। अपनी तरफ से अच्छा करो। तुम्हारा जैसा भी परीक्षा परिणाम आएगा हमें मंजूर होगा। बच्चों के सामने चिंतित चेहरा न रखें। अभिभावकों का चिंतित चेहरा देखकर बच्चे और अधिक तनाव अनुभव करेंगे। इससे जो वे याद किए हैं और पढ़े हैं, वह भूलने लगेंगे। परीक्षा की तैयारी के दौरान बच्चों को अच्छे पेन लाकर दें जो उनके लिए जरूरी है। यह बच्चों के तनाव को हल्का करने में सहायक होगा। बच्चों को तैयारी में सहायता जरूर करें पर दबाव न डालें। कठिनाइयों को शिक्षकों व सहपाठियों से साझा करें। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ नया पढ़ने या सीखने का नहीं है। जो वे पढ़ चुके हैं उसके रिविजन में जुट जाएं। विद्यार्थी उन विषयों और पाठ्यक्रम को पहचानने की कोशिश करें, जिनमें उन्हें कठिनाई आती है। इसके बाद शिक्षक या विषय के जानकार अन्य लोगों से मिलकर उन कठिनाइयों को दूर करें और माता-पिता व अभिभावक अपने बच्चे को भरोसा दिलाएं कि वे परीक्षा में बेहतर करेंगे। बच्चों का चंचल मन बहुत जल्दी दूसरी तरफ डायवर्ट हो जाता है। घर में पढ़ाई का माहौल बनाए रखें। इस दौरान शादी विवाह या अन्य आयोजनों में बच्चों का जाना अवाएड करें।बच्चों की कमजोरियों का भी दूसरे के सामने न प्रकट करें न ही उपहास उड़ाए। बल्कि उन्हें एकांत में बैठा करके उसे दूर करने का प्रयास करें। उनकी थोड़ी सी भी नाराजगी बच्चों की आलोचना या नकारात्मक कमेंट बच्चों के कंसंट्रेट को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होता है। बच्चों को उच्च मनोबल और उत्साह से परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करें। निसंदेह इससे वह बेहतर कर पायेंगे। अगर किसी कारणवस रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा तो यह न मानें की उनके लिए दुनिया खत्म नहीं हुई है। भले ही थोड़ी ही देर लगे लेकिन आप सही दिशा में ईमानदारी से पूरी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सफल होंगे। इसलिए सभी अभिभावकों की से हमारी अपील हैं कि विद्यार्थियों पर अधिक नंबर या परसेंटेज लाने के लिए अनावश्यक दबाव ना बनाएं।

योग एवं योगिक तेल मालिश कार्यशाला का हुआ आयोजन

योगिक तेल मालिश से अर्थाराइटिस एवं सभी त्वचा रोगों का होगा निवारण : के.के. अरोडा

मालिश विशेषज्ञ आचार्य कृष्ण कुमार अरोड़ा ने साधकों को योगिक वैज्ञानिक मालिश की व्यवहारिक विधि बताई और तेल मालिश पैरों के अंगूठे,उंगलियों, जॉइंट्स की मालिश क्लॉक वाइस एवं एंटी क्लॉक वाइस करवाई।

परिवहन विशेष न्यूज

ग़ाज़ियाबाद। अखिल भारतीय ध्यान योग संस्थान रजि.द्वारा चांसलर क्लब,चिरंजीविहार में 100 से अधिक साधकों को कार्यशाला में योग एवं वैज्ञानिक तेल मालिश का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

संस्थान के महामंत्री दयानंद शर्मा ने ओ३म की ध्वनि और गायत्री मंत्र से योग सत्र को प्रारंभ किया।उन्होंने साधकों को वीरेचन क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग भस्त्रिका तथा हाथों पैरों के सूक्ष्म अभ्यास करा कर उनके तन मन को ऊर्जावान बनाकर तेल मालिश के लिए तैयार किया तथा कहा स्वस्थ शरीर ही जीवन का आधार है।सभी सुखों का आनंद स्वस्थ शरीर से ही लिया जा सकता है।उन्होंने आगे बताया कि आयुर्वेद में भी मालिश को चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है,मालिश एवं घर्षण से हमारे शरीर के रोम कूप खुलते हैं तथा रक्त संचार बढता हैं।मालिश से न केवल शरीर को पुष्टि मिलती है अपितु अनेक रोगों का विनाश भी होता है।इस क्रिया द्वारा शरीर का तंत्रिका-तंत्र एवं रक्त संचरण तंत्र दुरूस्त एवं सक्रिय रहते है।

मालिश विशेषज्ञ आचार्य कृष्ण कुमार अरोड़ा ने साधकों को योगिक वैज्ञानिक मालिश की व्यवहारिक विधि बताई और तेल मालिश पैरों के अंगूठे,उंगलियों, जॉइंट्स की मालिश क्लॉक वाइस एवं एंटी क्लॉक वाइस करवाई।उन्होंने पैर के तलवों में प्रेशर प्वाइंट की मालिश प्रारंभ कराते हुए कहा कि यह मालिश आम मालिशों से हटकर अलग प्रकार की विशेष मालिश होती है क्योंकि यह विशेषकर मानव शरीर के 206 ज्वाइंट तथा पूर्ण शरीर को संचालित करने वाली सभी ग्लैंडस को अति सक्रिय करने वाली मालिश है जोकि रक्त परिवहन तंत्र को ठीक व सुचारू गति प्रदान करती है जिससे व्यक्ति हृदय रोग,त्वचा रोग व अर्थाराइट्स रोगों से बचा रहता है।अर्थाराइटिस एवं सभी त्वचा रोग निवारण में रामबाण का कार्य करती है वैज्ञानिक योगिक मालिश।उन्होंने हाथ की दूसरे हाथ से ट्रैम्पिंग,क्लिम्पिंग,बीटिंग, हैकिंग एवं नोचिन्ग कराने के बाद तेल को पूर्णतया सुखवा दिया

संस्थान के उपाध्यक्ष अशोक शास्त्री ने बताया कि आपको कम से कम अपनी नाभि,नासिका, छिद्रों,कर्ण छिद्रों तथा मलद्वार में प्रतिदिन अवश्य तेल लगाने का अनुरोध किया।

शिक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता ने सभी साधकों को 24 मार्च 2024 को औषधि पार्क राजनगर,सैक्टर 4 में फूलों एवं चंदन की होली के पावन त्यौहार के लिए आमंत्रित किया।

इस कार्यक्रम में संस्थान की कार्य कारणी सदस्यों तथा सभी योग कक्षाओं के शिक्षकों ने अपने साधकों के साथ बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

इस अवसर पर मुख्य रूप से सर्वश्री मनमोहन वोहरा,अशोक शास्त्री,नेतराम गौतम,प्रवीण आर्य,ललित अरोड़ा,डा प्रमोद सक्सेना,लक्ष्मण कुमार गुप्ता, चरत कुमार राजेश शर्मा,अशील कुमार आदि उपस्थित रहे।

शांतिपाठ एवं दुग्धाहार के साथ कार्यशाला सत्र संपन्न हुआ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code : DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023